● वर्ष : 17 ● अंक : 192 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

# दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का सम्मान

दिल्ली से प्रकाशित

रविवार 03 मई 2026

# एलपीजी सिलेंडरों की सौ फीसदी सप्लाई की जा रही सुनिश्चित

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सिलेंडर खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। घरेलू परिवारों को एलपीजी सिलेंडरों की 100 फीसदी सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। विदेश मंत्रालय खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि कल ऑनलाइन घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की बुकिंग बढ़कर 99 फीसदी हो गई, जबकि ओटीपी आधारित डिलीवरी 94 फीसदी से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि मार्च, 2026 से अब तक लगभग 5.96 लाख पीएनजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं और 2.68 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, इसके साथ ही लगभग 6.66 लाख ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। मंत्रालय ने कहा कि 9 अप्रैल, 2026 से मुंबई,

## आपूर्ति ठप होने की कोई रिपोर्ट नहीं : सरकार

कोच्चि, विजाग, चेन्नई, मथुरा और गुजरात की रिफाइनरियों ने रसायन, फार्मा और पेंट उद्योग को 10,000 मीट्रिक टन से अधिक प्रोपलीन और 1200 मीट्रिक टन से अधिक ब्यूटाइल एक्रिलेट बेचा है। वहीं, अबतक 2,922 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी हुई हैं, इनमें पिछले 24 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से सुरक्षित स्वदेश वापसी करने वाले 30 नाविक भी शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में बताते हुए कहा कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें। नागरिकों को वैकल्पिक ईंधन जैसे कि पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी (परिवहन) की 100 फीसदी आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी के लिए, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा फार्मा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को 5 किलोग्राम एफटीएल की आपूर्ति 2 और 3 मार्च 2026 को औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर दोगुनी कर दी गई है।

## वैश्विक कारणों से बढ़ी कमर्शियल एलपीजी की कीमतें, आयात पर निर्भर भारतः प्रह्लाद जोशी

**नई दिल्ली।** केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी का कारण वैश्विक कारकों को बताया, उन्होंने सरकार के फैसले का बचाव कर कहा कि भारत की एलपीजी की आधी से अधिक मांग आयात से पूरी होती है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा, यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, और हमारी 50 प्रतिशत से अधिक एलपीजी की निर्भरता आयात पर है। इसकारण वर्तमान में ये समस्या है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि जहां केंद्र सरकार ने अन्य ईंधनों की कीमतें अपरिवर्तित रखी हैं, वहीं वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में यह वृद्धि एक ऐसी चीज है, जिस सरकार दवारा टाला नहीं जा सकता था। हालिया बढ़ोतरी के बाद, 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में औसतन 993 रुपये का इजाफा हुआ है।

**ज्वलंत मुद्दा** **संपादकीय**

## सबसे महंगी रसोई गैस गरीबों को

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का मतदान 29 अप्रैल को जैसे ही खत्म हुआ उसके तुरंत बाद सरकार की सबसे बड़ी महंगाई की गाज गरीबों और मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ी है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 5 किलो के छोटे सिलेंडर में 261 रुपए की मूल्य वृद्धि कर दी है। भारत में यह सबसे महंगी गैस हो गई है जो 162 रुपए किलो गरीबों को खरीदनी पड़ेगी। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल रसोई गैस के सिलेंडर से ज्यादा छोटू सिलेंडर की रखी है। निदित रूप से 5 किलो वाले सिलेंडर की सप्लाई पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा की जा रही है। पिछले दो महीने में सरकार और पेट्रोलियम कंपनी ने 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के कनेक्शन बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। अमेरिका और ईरान युद्ध के बाद एलपीजी गैस की कमी होने के कारण सरकार ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। 5 किलो के छोटू सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों को 5 किलो के सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं। इसमें भी पेट्रोलियम कंपनी को कमाई हो रही है। गैस के दाम भी सबसे ज्यादा कर दिए हैं।

लाखों लोग रोजाना 5 किलो के सिलेंडर पेट्रोलियम कंपनियों से ले रहे हैं। 14 किलो वाले सिलेंडर की सप्लाई लगातार कम होती जा रही है। इसमें सरकार को सब्सिडी देना पड़ती है। दूसरा इसके लिए गैस भी पेट्रोलियम कंपनियों के पास ज्यादा होनी चाहिए। एक संयोजित रणनीति के तहत 14 किलो के गैस सिलेंडर के स्थान पर 5 किलो के गैस सिलेंडर की सप्लाई बढ़ा दी गई है। भारत में सबसे महंगी गैस गरीबों और मध्यम वर्ग को खरीदना पड़ रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19 किलो वाला है वह भी छोटू सिलेंडर की तुलना में कम कीमत पर पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा बेचा जा रहा है। रही सही कसर दो-चार दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को लेकर पूरी होने जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाने का संकेत दे दिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक माह में तीन से चार बार कीमत बढ़ाई जाएगी। 20 से 25 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे उसके बाद बड़ी तेजी के साथ हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ेगी। इसका खामियाजा भी सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग को ही भुगतना पड़ेगा।

इन्हीं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यही सबसे ज्यादा खाते हैं, पीते हैं, खर्च करते हैं और बोझ भी बहुत सारा सरकार इन्हीं पर डाल रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी निजी पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर बड़े मेहरबान हैं। पिछले 4 साल में जब कच्चे तेल के दाम कम थे, उस समय भी निजी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी को भारी मुनाफा कमाने का मौका दिया गया। रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल कम कीमत पर आयात किया गया। इसका लाभ भारत के उपभोक्ताओं को नहीं मिला। निजी कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल को खरीदकर उसे रिफाइन करके विदेशों में निर्यात किया और भारी मुनाफा कमाया। अभी भी सरकार पेट्रोलियम कंपनियों के ऊपर मेहरबान है।

**सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक**
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

## संक्षिप्त समाचार

### क्या आपके मोबाइल में भी बजा इमरजेंसी अलर्ट, घबराएं नहीं सरकार ने किया है आपदा चेतावनी सिस्टम का परीक्षण

**नई दिल्ली।** शनिवार की दोपहर करीब 11:42 बजे देशभर में लाखों स्मार्टफोन यूजर्स उस समय चौंक गए, जब उनके मोबाइल फोन अचानक तेज एसओएस जैसी आवाज के साथ बज उठे। कई लोगों के फोन पर एक साथ अलर्ट मैसेज फ्लैश हुआ, जिससे कुछ समय के लिए भ्रम और हल्की चिंता की स्थिति भी बन गई। हालांकि, यह कोई आपात स्थिति नहीं थी, बल्कि भारत सरकार द्वारा किए जा रहे एक महत्वपूर्ण तकनीकी परीक्षण का हिस्सा था। यह मैसेज हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में दिखाई दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यह स्वदेशी "सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम" का परीक्षण है। मैसेज में यूजर्स से अपील की गई थी कि वे इस टेस्ट के दौरान किसी प्रकार की कार्रवाई न करें। दरअसल, दूरसंचार विभाग (डीओटी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) मिलकर देश में मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदाओं, मौसम संबंधी चेतावनियों और अन्य आपात स्थितियों की जानकारी समय पर आम नागरिकों तक पहुंचाई जा सके।

### देशभर में 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' का परीक्षण, आपदा होने पर तुरंत मिलेगी सूचना

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों तक त्वरित सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' का आज यहां परीक्षण किया जिसमें सभी प्रकार के मोबाइल के स्क्रीन पर एक ही समय में एक मैसेज बॉक्स में आपात स्थिति का संदेश उभरता है तथा ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की बीप ध्वनि के साथ वाइबेट करता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह एक कार्यक्रम में रिमोट के माध्यम से इसके देशव्यापी परीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न किया। परीक्षण के तहत लगभग 11:45 बजे देशभर में मोबाइल फोन पर एक साथ बीप ध्वनि के साथ इमरजेंसी अलर्ट संदेश प्राप्त हुआ। संदेश में स्पष्ट किया गया कि यह एक परीक्षण है और जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यह अत्याधुनिक प्रणाली संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से विकसित की गई है, ताकि आपदा के समय नागरिकों तक महत्वपूर्ण सूचनाओं का समय पर प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। एनडीएमए ने दूरसंचार विभाग के प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) द्वारा विकसित एकीकृत अलर्ट सिस्टम 'सचेत' को सफलतापूर्वक चालू किया है। यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) पर आधारित है। वर्तमान में यह देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है और भौगोलिक रूप से लक्षित क्षेत्रों में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को एसएमएस के माध्यम से आपदा एवं आपातकालीन अलर्ट प्रदान कर रही है।

## अब कोई चारा नहीं बचा, कहकर एअर इंडिया ने फ्लाइट ऑपरेशन कम करने की तैयारी में

एजेंसी। नई दिल्ली

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण जेट फ्यूल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकारण कई एयलाइंस कंपनियों को मुनाफे में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, एअर इंडिया अपने फ्लाइट ऑपरेशन को कम करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एअर इंडिया जून और जुलाई के दौरान शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन को कम करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन का कहना है कि एअर इंडिया के लिए कई फ्लाइट्स घाटे का सौदा बनी है, इसकारण जून और जुलाई के शेड्यूल फ्लाइट में कटौती करने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। जेट फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में उछाल के कारण ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि एयर इंडिया के लिए कई इंटरनेशनल उड़ानें घाटे का सौदा बन गई हैं। एटीएफ की कीमतों में उछाल और मिडिल ईस्ट में जंग के कारण एयर इंडिया अपने कई इंटरनेशनल ऑपरेशन में कटौती कर रहा है। यह खबर तब आई है, जब एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने विदेशी एयरलाइंस के लिए इंटरनेशनल फ्यूल प्राइस में इजाफा किया है। इंटरनेशनल जेट फ्यूल की कीमतों में 5 फीसदी का इजाफा किया गया है। दरअसल, ईरान-अमेरिका जंग और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

# अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी तोड़ने के लिए बनाया अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का प्लान

एजेंसी। वॉशिंगटन

ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव अब एक नए और जटिल रणनीतिक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले दो महीनों से जारी इस संघर्ष की गति भले ही कुछ धीमी पड़ती दिख रही हो, लेकिन तनाव का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वर्तमान में इस टकराव का केंद्र दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बन गया है। ईरान द्वारा इस मार्ग पर की गई नाकेबंदी ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इस नाकेबंदी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ते नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए अब अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अमेरिकी प्रशासन अब सीधे सैन्य टकराव के बजाय कूटनीतिक और सामूहिक सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस नई रणनीति के तहत 'मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट' यानी समुद्री स्वतंत्रता संरचना नाम का एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने की तैयारी की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को फिर से सामान्य करना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग और अमेरिकी सेंट्रल कमान (सेंटकॉम) मिलकर काम करेंगे। जहाँ विदेश विभाग विभिन्न देशों और शिपिंग कंपनियों के साथ कूटनीतिक समन्वय करेगा, वहीं सेंटकॉम समुद्री गतिविधियों की निगरानी और जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा संभालेगा। दरअसल, फरवरी के अंत में हुए हमलों के बाद ईरान ने इस मार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, जिससे शिपिंग ट्रैफिक लगभग ठप हो गया है। दूसरी ओर, ईरान ने भी अमेरिका की इस घेराबंदी का जवाब देने के लिए फोन डिप्लोमेसी का सहारा लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और इराक जैसे क्षेत्रीय देशों के विदेश मंत्रियों से संपर्क कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

## युद्धपोत 'महेंद्रगिरि' 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से है लैस, नौसेना की ताकत में इजाफा

**नई दिल्ली।** पूरी तरह से स्वदेशी और अत्याधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत 'महेंद्रगिरि' को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इससे नौसेना की समुद्री ताकत में इजाफा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने इस युद्धपोत को तैयार किया है। नीलगिरि-श्रेणी का यह छठा युद्धपोत है। इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में ही हुआ है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मजबूती देता है। इसे दुश्मन की नजरों से बचने यानी स्टेल्थ क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। समुद्र में यह लंबे समय तक टिक सकता है और कई तरह के मिशन संभालने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक इस युद्धपोत को खास तौर पर खतरनाक बनाती हैं इसकी हथियार प्रणालियां। इसमें दूर तक मार करने वाली आठ ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा सतह से सतह पर मार करने वाली बराक मिसाइल प्रणाली भी मौजूद है। पनडुब्बियों से निपटने के लिए इसमें टॉरपीडो और रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं, जो इसे उन्नत युद्ध क्षमता से लैस बनाते हैं। 'स्टेल्थ' तकनीक का मतलब है छिपने की कला। इससे बने युद्धपोतों को दुश्मन के रडार आसानी से पकड़ नहीं पाते।

## बंगाल-फालता में लोगों का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप

**कोलकाता** । पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के 4 और मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों पर शनिवार सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान जारी है। डायमंड हार्बर के फालता में स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। इन लोगों का कहना है कि वोट डालने के बाद उन पर TMC कार्यकर्ताओं ने हमला किया और मारपीट की है। जब वे इसका शांति से विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोट आई है। लोगों ने विशेष समुदाय पर हमले का आरोप लगाया है। वहीं, TMC ने आरोप लगाया कि मगराहाट के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षाबलों ने हमारे कैंप में तोड़फोड़

की और कार्यकर्ताओं से मारपीट की। घटना के बाद TMC समर्थकों ने नारेबाजी की है। डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम में दोपहर 1 बजे तक 55% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वहीं चुनाव आयोग ने बंगाल में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। दरअसल, 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान EVM से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी। इसके चलते दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया।

## स्पिरिट एयरलाइंस 34 साल बाद हुई बंद, सभी उड़ानें रद्द, 17 हजार नौकरियों पर संकट

एजेंसी। नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी संकट और तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अत्यंत कम लागत वाली अमेरिकी एयरलाइंस कंपनी स्पिरिट एयरलाइन ने 34 साल बाद अपने परिचालन को तुरंत प्रभाव से बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी ने अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं और ग्राहक सेवा को बंद कर दिया गया है। एयरलाइन के इस कदम से 17 हजार लोगों की नौकरियां जाने का खतरा है। स्पिरिट एयरलाइंस ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि उसकी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि व्हाइट हाउस से संभावित बेलआउट न मिल पाने के बाद उसने अपने ऑपरेशन्स को व्यवस्थित तरीके से बंद करना शुरू कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। एयरलाइन ने कहा स्पिरिट की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। स्पिरिट एविएशन होल्डिंग्स, इंक, जो स्पिरिट एयरलाइंस की मूल कंपनी है, उसने 500 मिलियन डॉलर की बचाव डील हासिल करने में नाकाम रहने के बाद अपना कामकाज बंद कर दिया है। दरअसल, बढ़ती ईंधन कीमतों और ईरान युद्ध के असर से कंपनी पहले ही वित्तीय संकट और दिवालियापन से जूझ रही थी। इस बंदी से करीब 17 हजार कर्मचारियों की नौकरियों पर असर पड़ सकता है और विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा घटने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्पिरिट एयरलाइंस ने आज खेद के साथ घोषणा की है कि कंपनी ने अपने परिचालन को व्यवस्थित रूप से बंद करना शुरू कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है।

# लद्दाख पहुंचे अमित शाह, वांगचुक समेत प्रमुख नेताओं से की मुलाकात

एजेंसी। लेह

पर्यावरणविद् और लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात लेह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की उनके साथ लद्दाख के कई अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद थे। यह मुलाकात मुख्य रूप से भगवान बुद्ध और आध्यात्मिकता पर केंद्रित रही। केंद्रीय गृह मंत्री शाह भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने लद्दाख के नेताओं के साथ बैठक की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में अमित शाह ने नेताओं से भगवान बुद्ध में विश्वास बनाए रखने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक

**सब कुछ ठीक हो जाएगा, 22 मई को उप-समिति की बैठकः गृहमंत्री**

हो जाएगा। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के पूर्व मुख्य कार्यकारी ग्यालसन भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यह बैठक गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई थी। शाह ने स्पष्ट किया कि उनकी यह यात्रा पूरी तरह से आध्यात्मिक है और वे यहां भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन करने आए हैं। शाह ने लद्दाख के नेताओं को सूचित किया कि लद्दाख से जुड़े मुख्य मुद्दों पर 22 मई को गृह मंत्रालय की एक उप-समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। ग्यालसन के मुताबिक शाह ने नेताओं से कहा कि वे 22 मई की बैठक में खुले दिमाग से आएं और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यदि इस उप-समिति की बैठक में कोई आम सहमति बनती है, तो बाद में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस 30 मिनट की बैठक में एलएबी के सह-अध्यक्ष त्सेरिंग दोरजे लकरूक और लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा भी मौजूद थे। लकरूक ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री के सामने कई मांगें रखीं।

## मई की संभावित गर्मी से घबराने की जरूरत नहीं: जितेंद्र सिंह

**नई दिल्ली।** केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मई महीने में संभावित गर्मी और लू को लेकर जनता से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। मौसम पूर्वानुमान को सही ढंग से समझकर और दिन-प्रतिदिन की सरल सावधानियों से प्रभाव को कम किया जा सकता है। डॉ. सिंह ने शनिवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और हीटवेव की स्थिति बन सकती है, लेकिन यह पूरे देश में समान रूप से प्रभावी नहीं होगी। समय पर तैयारी और आईएमडी द्वारा समय-समय पर जारी सलाहों का पालन करके इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। डॉ. सिंह ने लोगों को सलाह दी कि वे पर्याप्त पानी पिएं, दोपहर की धूप से बचें और बच्चों, बुजुर्गों एवं बाहरी काम करने वालों का विशेष ध्यान रखें।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
( 9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

## ख़ास ख़बर

### मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, निर्वाचन आयोग ने सर्कुलर के पालन का दिया भरोसा

**लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली।** निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय को आश्वस्त किया है कि पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संबंधी जारी सर्कुलर का पूर्णतः पालन किया जाएगा। यह आश्वासन शनिवार को हुई विशेष सुनवाई के दौरान दिया गया। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दमा शेषाद्री नायडु ने पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ को बताया कि 4 मई को होने वाली मतगणना के दौरान राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि इस संबंध में अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें मतगणना कार्य के लिए केवल केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई थी कि राज्य सरकार और राज्य के केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इससे पहले, इसी मुद्दे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई थी, जिसे 30 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि मतगणना के लिए पर्यवेक्षकों और सहायकों की नियुक्ति का अधिकार निर्वाचन आयोग के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय के इसी निर्णय को चुनौती देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने अब उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए सर्कुलर के पालन का भरोसा दिलाया।

### अंतरराष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे कीर्तिवर्धन सिंह

**लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली।** विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह अमेरिका के न्यूयॉर्क में 4 से 8 मई तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले दूसरे अंतरराष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच (आईएमआरएफ) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच (आईएमआरएफ) प्रवासन पर वैश्विक समझौते के कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों के साथ इसके अंतर्संबंध पर चर्चा और प्रगति साझा करने के लिए प्राथमिक अंतर-सरकारी वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। दूसरा आईएमआरएफ 2022 में आयोजित पहले आईएमआरएफ की निरंतरता में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और अपने प्रवासी समुदाय के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार इसमें चार संवादात्मक बहु-हितधारक गोलमेज सम्मेलन, एक नीतिगत बहस और एक पूर्ण सत्र शामिल होंगे। इसके परिणामस्वरूप एक प्रगति घोषणा को अपनाया जाएगा। यात्रा के दौरान सिंह न्यूयॉर्क में आयोजित आईएमआरएफ के पूर्ण सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे। भारत आईएमआरएफ के दौरान 'प्रवासन शासन में डिजिटल नवाचार का लाभ उठाना - भारत का ई-माइग्रेट अनुभव' शीर्षक से एक सह-कार्यक्रम का आयोजन और मेजबानी भी करेगा। इस यात्रा के दौरान राज्यमंत्री के आईएमआरएफ में भाग ले रहे अन्य सदस्य देशों के वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और मंत्रियों से भी मुलाकात करने की संभावना है।

### गीतकार प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के अध्यक्ष

**लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली।** केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से शनिवार को एक जारी बयान में यह जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष नवनीत सहगल ने गत चार दिसंबर को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तब से यह पद खाली था। रेल, सूचना प्रसारण, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नियुक्ति पर प्रसून जोशी को बधाई दी। उन्होंने कहा, "प्रसून जोशी को साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। प्रसून एक विलक्षण रचनात्मक व्यक्तित्व हैं, जिन्हें विज्ञापन, साहित्य, कला और सिनेमा जगत में विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है, फिर भी उनका हृदय भारत के लिए धड़कता है। उनके शब्दों में हमारी मिट्टी की सुगंध समाई है और उनकी दृष्टि हमारी संस्कृति के शाश्वत सार को प्रतिबिंबित करती है। उनके नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक दृष्टि मिलेगी।" इस नियुक्ति से पहले, प्रसून जोशी अगस्त 2017 से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष रहे हैं, जहां उन्होंने फिल्म उद्योग के सभी हितधारकों के साथ जुड़कर फिल्म प्रमाणन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने में योगदान दिया। इससे पहले, वे मैक्कैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के सीईओ और मैक्कैन वर्ल्ड ग्रुप एशिया पैसिफिक (मैक्कैन एरिक्सन की सहायक कंपनी) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे 2016 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यासियों में से एक हैं। उल्लेखनीय है कि प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है, जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से देशभर में समाचार, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है।

### पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती

**लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली।** चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। आयोग ने कहा है कि अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि मतगणना प्रक्रिया सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हो। चुनाव आयोग के अनुसार ये नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 20बी के तहत ईसीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई हैं। इस अवधि के दौरान पर्यवेक्षकों को आयोग के प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे। अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उन 165 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता के लिए की गई है जिनमें एक से अधिक मतगणना हॉल हैं। पुलिस पर्यवेक्षक अपने-अपने निर्धारित मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा और कानून व्यवस्था की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था आयोग के निर्देशों के अनुसार हो। हालांकि, मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पुलिस पर्यवेक्षक मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात मतगणना पर्यवेक्षकों और अन्य चुनाव मशीनरी के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करेंगे।

# दिल्ली को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा : रेखा गुप्ता

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को पर्यटन हितधारक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में पर्यटन, आतिथ्य, विरासत, आध्यात्मिक, डिजिटल, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, नाइट टूरिज्म और दिल्ली की ब्रैंड पोजिशनिंग जैसे अहम विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को अब केवल ट्रांजिट हब के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दिल्ली के कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के प्रबंध निदेशक सुनील अंचिपाका सहित पर्यटन व अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई विशेषज्ञ भी शामिल हुए।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में उद्योग जगत, नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी से कई ठोस और उपयोगी सुझाव सामने आए हैं। इन सुझावों और फीडबैक को आगामी नीतियों और योजनाओं में शामिल किया जाएगा ताकि दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा दी जा सके और इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली का वैश्विक स्तर पर विशेष महत्व है। भारत आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक प्रमुख आकर्षण बन सकती है। अब समय आ गया है कि दिल्ली को केवल एक गुजरने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी डेस्टिनेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाए, जहां पर्यटक ठहरें, अनुभव लें और बार-बार लौटकर आएं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि यहां संसद, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसे प्रतिष्ठित शक्ति केंद्र स्थित हैं। साथ ही लाल किला, कुतुब मीनार सहित समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर, विविध संस्कृति और देशभर की झलक तथा दिल्ली का अनूठा और विविधतापूर्ण खानपान इसे एक सम्पूर्ण पर्यटन अनुभव प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी की सकारात्मक ब्रैंडिंग पर विशेष जोर दे रही है ताकि इसे पर्यटन के साथ-साथ चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि देश और दुनिया भर से अधिक से अधिक लोग दिल्ली आएं, यहां ठहरें और यहां के अनुभवों को अपने साथ लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बड़े कॉन्सर्ट, फिल्म फेस्टिवल और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा दे रही है, जिससे दिल्ली की वैश्विक पहचान मजबूत हो रही है। साथ ही फिल्म नीति और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योग को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) द्वारा पर्यटन क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डीटीटीडीसी ने अगोडा, मेक माई ट्रिप फाउंडेशन और सभ्यता फाउंडेशन के साथ साझेदारियां की हैं, जो डिजिटल इनोवेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अवसंरचना विकास और सतत पर्यटन को बढ़ावा देंगी। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और यह सम्मेलन राजधानी के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से दिखाई देंगे।दिल्ली के कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को एक विश्वस्तरीय पर्यटन हब बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। दिल्ली टूरिज्म बोर्ड के गठन, सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था, प्रमुख प्रवेश द्वारों के सौंदर्यीकरण, यूनिटी मॉल के निर्माण और दिल्ली की विरासत, संस्कृति व खानपान को एकीकृत कर नए पर्यटन अनुभव विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली को एक विशिष्ट वैश्विक पर्यटन गंतव्य बनाया जाएगा, ताकि बदलते भारत का चेहरा दिल्ली बने। कपिल मिश्रा के अनुसार सम्मेलन के दौरान प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को आगामी नीतियों और योजनाओं में शामिल किया जाएगा, ताकि दिल्ली को पर्यटन, संस्कृति और आतिथ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके।

## कटेवड़ा गांव में विकास को मिली रफ्तार : रविंद्र इंद्राज सिंह

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज कटेवड़ा गांव में फिरनी रोड एवं आरसीसी नाले के निर्माण कार्य की शुरूआत करके नई रफ्तार दी है। उन्होंने कह कि यह कार्य दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के फंड से कराया जा रहा है। मंत्री इंद्राज ने कहा कि ग्राम विकास बोर्ड के माध्यम से क्षेत्र में कई अन्य विकास योजनाएं भी लगातार चलाई जा रही हैं, जिससे पूरे बवाना विधानसभा क्षेत्र में व्यापक विकास देखने को मिल रहा है। इन कार्यों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। मंत्री इंद्राज सिंह ने कहा कि गांव–देहात के विकास को प्राथमिकता देना उनकी जिम्मेदारी है और वे निरंतर प्रयासरत हैं कि प्रत्येक गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्राम विकास बोर्ड के माध्यम से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।उन्होंने आगे कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचा और बेहतर कनेक्टिविटी ही विकास की नींव है तथा इसी दिशा में निरंतर कार्य करते हुए "विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली" के संकल्प को साकार किया जा रहा है।

## ऑनलाइन पुरानी कार बेचने के नाम पर दो लाख की ठगी, आरोपित गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** ऑनलाइन सेकेंड हैंड कार बेचने का झांसा देकर दो लाख रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपित को पूर्वी जिला साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित का नाम अमन सेठी है। वह खुद को नामी ऑनलाइन कार सेल-पर्चेज प्लेटफॉर्म का कर्मचारी बताकर लोगों को भरोसे में लेता था और बुकिंग एवं प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा लेता था। पुलिस ने बताया कि त्रिलोकपुरी निवासी पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना ईस्ट में 16 अप्रैल 2026 को ई-एफआईआर संख्या 127/26 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे एक व्यक्ति ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सेकेंड हैंड कार बेचने का प्रस्ताव दिया और भरोसा जीतकर बुकिंग व प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर दो लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। रकम लेने के बाद आरोपी ने न तो कार दी और न ही पैसे लौटाए। बाद में उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को बताया कि मामले की जांच के दौरान साइबर थाना पुलिस की टीम ने बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल फुटप्रिंट खंगाले। जांच में पता चला कि ठगी की रकम भारतीय स्टेट बैंक के एक खाते में ट्रांसफर हुई थी। खाते की केवाईसी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपित की पहचान अमन सेठी के रूप में हुई। पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना ठिकाना बदल चुका था। आखिरकार तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित पहले भी इसी तरह के एक ठगी के मामले में शामिल रह चुका है, जो कृष्णा नगर थाने में दर्ज है। पुलिस अब उसके अन्य साथियों और पूरे मनी ट्रेल की जांच कर रही है।पुलिस के मुताबिक आरोपित ऑनलाइन सेकेंड हैंड कार तलाश रहे लोगों को निशाना बनाता था। वह खुद को प्रतिष्ठित कार बिक्री प्लेटफॉर्म का कर्मचारी बताकर कार की तस्वीरें और डिटेल भेजता, फिर बुकिंग या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर एडवांस मांगता। रकम मिलते ही संपर्क तोड़ देता था।

शांति सेवा न्याय
Delhi Police
SHANTI SEWA NYAY

## लाल किला ब्लास्टः अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** दिल्ली के साकेत कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।कोर्ट ने 30 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 6 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला के पास ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर थी। लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई। ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दो एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरु की थी। एफआईआर में कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता मिल चुकी है। ईडी ने कहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तौर पर जब्त कर लिया है। लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे। यूजीसी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। यूजीसी की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

## दिनदहाड़े पांच लाख की लूट का खुलासा, दो बदमाश गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** दिल्ली सनलाइट कॉलोनी इलाके में दिनदहाड़े पांच लाख रुपये की लूट और फायरिंग की वारदात का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका एक साथी अब भी फरार है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटी गई 3.92 लाख रुपये की नकदी, पीड़ित का मोबाइल फोन, एक देसी पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, बटनदार चाकू और वारदात में इस्तेमाल स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बिजेंद्र यादव (32) निवासी बागपत, उप्र और पवन गिरी (32) निवासी मेरठ, उप्र के रूप में हुई है। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है और कई गंभीर मामलों में पहले भी नाम सामने आ चुका है।क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त संजीव यादव ने शनिवार को बताया कि 25 अप्रैल की शाम करीब 6:40 बजे शिकायतकर्ता शाकिर अली अपने साले जीशान के साथ काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर जा रहे थे। जीशान के पास एक बैग में पांच लाख रुपये नकद थे, जो वह पुरानी दिल्ली स्थित एक रिश्तेदार से लेकर लौट रहे थे। जैसे ही वे सनलाइट कॉलोनी इलाके में पहुंचे, स्पोर्ट्स बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें घेरकर रोक लिया। बदमाशों में दो के हाथ में पिस्टल और एक के पास चाकू था। आरोपितों ने नकदी से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जीशान ने विरोध किया। विरोध होते ही एक बदमाश ने शाकिर अली के पेट में गोली मार दी, जबकि दूसरे ने जीशान पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों के घायल होने के बाद आरोपित बैग में रखे पांच लाख रुपये और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पहले होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। शिकायत के आधार पर सनलाइट कॉलोनी थाने में लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस उपायुक्त के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल को सौंपी गई। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय इनपुट जुटाए। जांच के दौरान 1 मई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वारदात में शामिल आरोपित आई.पी. पार्क रिंग रोड के पास आने वाले हैं। सूचना के आधार पर एसीपी पंकज अरोड़ा की देखरेख में टीम गठित कर जाल बिछाया गया। करीब 7:30 बजे स्पोर्ट्स बाइक पर आए दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। इसी दौरान आरोपित पवन गिरी ने पुलिस टीम पर पिस्टल तान दी, लेकिन हेड कांस्टेबल विनीत ने साहस दिखाते हुए उससे हथियार छीन लिया और दोनों आरोपितों को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपित पवन के पास से 1.94 लाख रुपये नकद, लूटा गया मोबाइल फोन और देशी पिस्टल बरामद हुई। वहीं बिजेंद्र के पास से 1.98 लाख रुपये नकद और बटनदार चाकू बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि बरामद नकदी लूट की रकम में उनका हिस्सा है और बरामद पिस्टल का इस्तेमाल ही वारदात में किया गया था।

**वारदात से पहले की थी रेकी:** आरोपितों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने वारदात से पहले पीड़ितों की गतिविधियों की रेकी की थी। उन्हें पहले से जानकारी थी कि पीड़ित बड़ी रकम लेकर निकलने वाले हैं। इसके बाद योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल तीसरा आरोपित संजय अभी फरार है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। वहीं पूछताछ में यह भी सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल की गई स्पोर्ट्स बाइक वर्ष 2024 में सहारनपुर (उप्र) से छीनी गई थी। इस संबंध में वहां भी मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार बिजेंद्र यादव पहले आबकारी अधिनियम के दो मामलों और हत्या के प्रयास के एक मामले में शामिल रहा है। वहीं पवन गिरी मेरठ के एक हत्या के मामले में आरोपी है और फिलहाल जमानत पर बाहर था।

## तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज होने पर भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की याचिका को खारिज करते हुए चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संवैधानिक हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने स्वागत किया है और टीएमसी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि जिस प्रकार तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल और निराधार आरोपों को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, वह उसकी "बौखलाहट और छटपटाहट" को दर्शाता है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव आगे बढ़ा, वैसे-वैसे टीएमसी का जनसमर्थन और मनोबल लगातार गिरता गया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और हिंसा-मुक्त मतदान संपन्न होने के बाद पार्टी में बेचैनी और अस्थिरता और बढ़ गई, जबकि एग्जिट पोल के रुझानों ने स्थिति को और स्पष्ट कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि इसके बाद टीएमसी ने बिना आधार वाले मुद्दों को उठाकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो उनकी राजनीतिक हताशा का संकेत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले 10 से 12 वर्षों में टीएमसी ने न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर 80 से अधिक बार अपील की है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उनके अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने आज संवैधानिक दृष्टिकोण से चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि कपिल सिब्बल द्वारा दायर याचिका भी खारिज कर दी गई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आईपीएसी कार्यालय पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री का स्वयं मौके पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि उन्हें अपने ही सहयोगियों पर पूर्ण भरोसा नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि कपिल सिब्बल, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और राजनीतिक रूप से टीएमसी के प्रति झुकाव रखते हैं, उनकी याचिका का भी अदालत ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय संवैधानिक दृष्टि से पूरी तरह उचित है, हालांकि राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से यह टीएमसी के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

## वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को किया अधिसूचित

लोकतंत्र की शान

**नई दिल्ली।** वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्वचालित मार्ग के तहत बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अधिसूचित कर दिया है, जो पिछले 74 फीसदी की सीमा को प्रतिस्थापित करती है।वित्त मंत्रालय की ओर से 2 मई 2026 को स्वचालित मार्ग के तहत बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई की अधिसूचना जारी की गई है, जो पिछले 74 फीसदी की सीमा को प्रतिस्थापित करती है। यह नियम सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक-2025 के तहत आया है, जिसका उद्देश्य विदेशी पूंजी, तकनीक और बेहतर उत्पाद लाना है। हालांकि एलआईसी के लिए यह सीमा 20 फीसदी ही रहेगी। अधिसूचना के मुताबिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) (द्वितीय संशोधन) नियम-2026 के अनुसार बीमा कंपनियों और ब्रोकरों सहित बिचौलियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति होगी। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए ये सीमा 20 फीसदी तय की गई है। उल्लेखनीय है कि संसद ने दिसंबर 2025 में सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक-2025 को पारित किया था। इसने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को पहले के 74 फीसदी से बढ़ाकर स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत करने का रास्ता साफ किया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया था। इसके बाद फरवरी 2026 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को अधिसूचित किया था।

## संक्षिप्त समाचार

### बीजेपी जन कल्याण मंच के जिला अध्यक्ष ने विभिन्न लोगों को सौपी संगठन की जिम्मेदारी

**लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः** शनिवार को बीजेपी जन कल्याण मंच अमरोहा के जिला अध्यक्ष भीष्म सिंह खड़कवंशी ने अपने कैंप कार्यालय पर संगठन का विस्तार करते हुए दर्जनों लोगों को संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपी जिसमें विक्रम सिंह को विधानसभा मंत्री हसनपुर, नेमचंद सिंह खड़कवंशी को ब्लॉक महामंत्री हसनपुर, जगपाल सिंह खड़कवंशी को ब्लॉक उपाध्यक्ष हसनपुर की जिम्मेदारी दी गई, साथ ही अनीस अली को ब्लॉक उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा तथा टीटू खड्गवंशी को युवा मोर्चा विधानसभा उपाध्यक्ष हसनपुर नियुक्त किया गया तथा भोजराम सिंह को तहसील मंत्री हसनपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई, इस अवसर पर उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारी से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा 2027 के चुनाव में अभी से जुट जाने का आह्वान किया,

### संपूर्ण समाधान दिवस में D M/S P ने सुनी शिकायतें, 70 में से 9 शिकायतों को हुआ निस्तारण

**लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः** शनिवार को करनपुर स्थित नवनिर्मित तहसील के सभागार कक्ष में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमे जिलाधिकारी नितिन गौड़ तथा पुलिस अधीक्षक लाखन सिंह यादव ने समाधान दिवस में आए फरियादियों की फरियाद सुनी और उनके निस्तारण के आदेश दिए, बताते चलें कि जिलाधिकारी अमरोहा एवं पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व में लगाए गए संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों की 70 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 9 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही करा दिया गया, बाकी अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों व लेखपालों को सभी शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने के आदेश दिए, संपूर्ण समाधान दिवस में आई शिकायतों में राजस्व विभाग की 26, पुलिस विभाग की 15, चकबंदी विभाग की 9, विकास विभाग की 10 एवं अन्य विभागों से संबंधित 10 शिकायतो सहित 70 शिकायते प्राप्त हुई, वही ग्राम तहारपुर निवासी एक बुजुर्ग महिला ने एक माह से हसनपुर की पुरानी गैस एजेंसी पर चक्कर लगाने के बाद भी गैस न मिलने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, वहीं जिलाधिकारी ने प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को बुजुर्ग महिला को गैस की होम डिलीवरी सुनिश्चित कराने के आदेश दिए, इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन गौड़, पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव, एसडीएम हिमांशु उपाध्याय, जिला पूर्ति अधिकारी प्रीति सिंह, खंड विकास अधिकारी विजय कुमार सक्सेना, पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज कुमार त्यागी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी गण मुख्य रूप से मौजूद रहे।

### नजीबाबाद में "उस्मानिया दवाखाना" का भव्य उद्घाटन खुर्शीद मंसूरी ने फीता काटकर किया शुभारंभ

**लोकतंत्र की शान , ख़िज़र अहमद , नजीबाबाद।** शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देते हुए "उस्मानिया दवाखाना" का शुभ उद्घाटन बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चेयरमैन साहनपुर खुर्शीद मंसूरी ने फीता काटकर दवाखाने का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि यूनानी तिब्ब पर आधारित इस प्रकार के दवाखाने समाज के लिए बेहद लाभकारी हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और सुरक्षित इलाज आज के समय की जरूरत है और इस दवाखाने के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। दवाखाने के संचालक हकीम मुहम्मद उस्मान ने सभी अतिथियों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि यहां यूनानी तिब्ब-ए-नबवी के अनुसार इलाज किया जाएगा, जिसमें मरीजों को बेहतर और सुरक्षित उपचार के साथ उचित परामर्श भी दिया जाएगा। यह दवाखाना स्टेशन वाली मस्जिद के नीचे, गुरु नानक लॉज के सामने, स्टेशन रोड, नजीबाबाद में स्थित है। उद्घाटन के अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन दुआओं के साथ हुआ, जिसमें दवाखाने की कामयाबी और लोगों की सेहत के लिए दुआ की गई।

### रामपुर-जिलाधिकारी और पुलिस अधिक्षक की अगुवाई में समाधान दिवस का आयोजन

**मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर /उत्तर प्रदेश** सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के निदान को लेकर तहसील समाधान दिवस और थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है इसी क्रम में जनपद रामपुर की तहसील सदर सभागार में डीएम अजय कुमार द्विवेदी और एसपी सोमेंद्र मीणा की अगवाई में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। रामपुर जनपद की तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की कमान डीएम अजय कुमार द्विवेदी के हाथ में रही वही इस मौके पर एसपी सोमेंद्र मीणा ने भी इसमें शिरकत की है। कुल मिलाकर दो दर्जन से अधिक शिकायतों को दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सुना गया जिनमें से कुछ शिकायत तो का मौके पर ही निसरण कराया गया है जबकि शेष समस्याओं के निदान के लिए मातहतो को निर्देशित किया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस में ज्यादातर शिकायतें राजस्व एवं राशन कार्डों से संबंधित आई हैं। **बाइट-अजय कुमार द्विवेदी/ डीएम रामपुर**

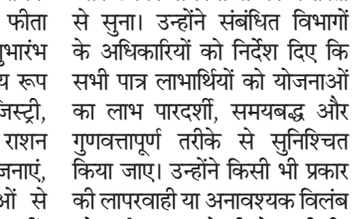

# रामपुर चाठा में हाथी का हमला: महिला की मौत

**वन विभाग पर उठे सवाल**

**लोकतंत्र की शान , खिज़र अहमद**

**नजीबाबाद।** तहसील क्षेत्र के मंडावली थाना अंतर्गत ग्राम रामपुर चाठा में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव निवासी ब्राह्मवती (पत्नी सुरेंद्र सैनी, उम्र लगभग 47 वर्ष) सुबह करीब 6 बजे अपने घर से कालू के डेरे पर दूध लेने के लिए निकली थीं। इसी दौरान अचानक एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला को संभलने का कोई अवसर नहीं मिला और हाथी ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों के बावजूद विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर मंडावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उपनिरीक्षक संजय यादव सहित पुलिस टीम ने हालात को संभालने का प्रयास किया। वहीं, वन विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई व मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। काफी देर तक चले हंगामे और समझाइश के बाद ग्रामीणों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की अनुमति दी। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

## औद्योगिक विकास के लिए मिशन मोड में पूरा कराएं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएंः मुख्यमंत्री

**लोकतंत्र की शान**

**लखनऊ** :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब और शहरी परियोजनाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां भी प्रक्रियात्मक बाधाएं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर करते हुए परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित की जाए। शनिवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इकाई का शिलान्यास होने जा रहा है। इसके पूर्व चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की वित्तीय निविदा का कार्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने चित्रकूट लिंक, फर्रुखाबाद लिंक और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों से अद्यतन जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन एक्सप्रेसवे के लिए आगामी 31 मई तक 90% भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। जहां रेट रिवीजन आवश्यक हो, वहां प्रस्ताव तत्काल भेजे जाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 15 दिन बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भूमि-स्वामियों से सीधा संवाद किया जाए। उन्हें उचित मुआवजा मिले और रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त मैनपॉवर तैनात कर कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी लिंक तथा मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए।

## समाज कल्याण के लिए तत्पर योगी सरकार, त्वरित कार्रवाई से बढ़ा भरोसा

**लोकतंत्र की शान**

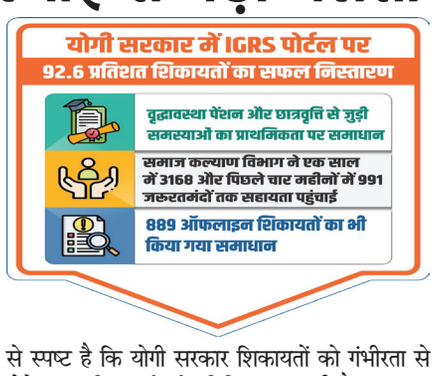


**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। समाज कल्याण विभाग की योजनाएं और शिकायत निवारण व्यवस्था आम जनता के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनकर उभरी हैं। खासकर आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम) पोर्टल के जरिए शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण ने प्रशासनिक कार्यशैली में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। इससे न केवल लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो रहा है, बल्कि सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है।

**ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर विभाग सक्रिय**-समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज 9604 शिकायतों में से 8896 यानी 92.6 प्रतिशत मामलों का सफल निस्तारण किया जा चुका है। यह उपलब्धि विभाग की कार्यकुशलता और जवाबदेही को दर्शाती है। वहीं, ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में भी विभाग ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले दो वर्षों में आई 1035 शिकायतों में से 889 का समाधान कर 85.9 प्रतिशत की सफलता दर हासिल की गई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि योगी सरकार शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।

**वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति पर विशेष फोकस**-सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है। इससे बुजुर्गों और छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है, जो उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये योजनाएं काफी सहायक साबित हो रही हैं। विभाग की कोशिश है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ पाने में देरी या परेशानी का सामना न करना पड़े।

## राष्ट्रीय युवा वाहिनी नेशनल वालंटियर भाजपा में नई नियुक्ति - पूनम द्विवेदी जी बनीं राष्ट्रीय सचिव, महिला संस्कृति प्रकोष्ठ (भारत)नई दिल्ली

**लोकतंत्र की शान,स्टेट ब्यूरो अवनीत कुमार शर्मा**

**लखनऊ/ राजधानी/**राष्ट्रीय युवा वाहिनी नेशनल वालंटियर भाजपा के संगठन विस्तार एवं भारतीय संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से पूनम द्विवेदी जी को राष्ट्रीय सचिव, महिला संस्कृति प्रकोष्ठ (भारत) के पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू देव प्रकाश शुक्ला जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में की गई है।

**पूनम द्विवेदी जी का योगदान और नई भूमिका-** पूनम द्विवेदी जी लंबे समय से भारतीय संस्कृति के संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय हैं। उनकी नियुक्ति से महिला संस्कृति प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊर्जा, सांस्कृतिक दिशा और संगठनात्मक मजबूती प्राप्त होगी।

**राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश-** "पूनम द्विवेदी जी जैसी समर्पित और संस्कारवान कार्यकर्ता का राष्ट्रीय दायित्व में आना संगठन के लिए गर्व का विषय है। उनका योगदान भारतीय संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को नई गति देगा।"

**संगठन का उद्देश्य-राष्ट्रीय युवा वाहिनी नेशनल वालंटियर भाजपा का संकल्प है —** गौ, गंगा, गीता, गायत्री, मठ और मंदिर की रक्षा करते हुए भारत को वैदिक सनातन राष्ट्र बनाना। संगठन पूरे देश में संस्कारशाला स्थापना, संस्कृति संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय है। संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी, महिला संस्कृति प्रकोष्ठ परिवार एवं संगठन के सभी पदाधिकारियों ने पूनम द्विवेदी जी को उनकी नई जिम्मेदारी पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

**रिपोर्ट : संगठन मीडिया प्रकोष्ठ**

**राष्ट्रीय युवा वाहिनी नेशनल वालंटियर भाजपा**

**जय हिंद - जय सनातन -**

## कमर्शियल सिलेंडर के दामों की वृद्धि को लेकर व्यापारियों ने सरकार के विरोध में सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई

**लोकतंत्र की शान, स्टेट ब्यूरो अवनीत कुमार शर्मा**

**लखनऊ/ राजधानी/संयुक्त** उद्योग व्यापार मंडल राजाजीपुरम के पीड़ित व्यापारियों ने फोन करके मार्केट की विभिन्न समस्याओं को संगठन के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे को अवगत कराया मार्केट के व्यापारियों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष मौके पर पहुंचे व्यापारियों ने कमर्शियल सिलेंडर के बढे रेट को लेकर नाराजगी व्यक्ति की और शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया कहा शासन प्रशासन व्यापारी विरोधी नीतियों के कारण व्यापार करना बहुत मुश्किल हो रहा गया है कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 993 रुपए अधिक होने से होटल रेस्टोरेंट ढाबा मिठाई मैरिज लॉन कैटर्स टेंट के व्यापारियों का कारोबार चौपट हो जाएगा यदि व्यापारी रेट बढ़ता हैं तो जनता भ्रमित होगी जिसका असर व्यापारी के साथ आम जनमानस पर भी बुरा पड़ेगा वहीं कुछ व्यापारियों ने बताया लखनऊ आवास विकास द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है पुराने बने मकान का नक्शा पास कराओ कमर्शियल रजिस्ट्री कराओ नहीं तो दुकान मकान सील कर दिया जाएगा यह सब दबाव देकर लाखों की वसूली आवास विकास कर रहा है व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे ने लखनऊ जिला ए डी एम आपूर्ति व आवास विकास को तत्काल मिलने के लिए फोन किया व्यस्तता के कारण दोनों विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को मिलने के लिए समय दिया तब व्यापारी शांत हुए संगठन के पदाधिकारी व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सोमवार को एडीएम जिला आपूर्ति एवं आवास विकास के एमडी से मिलेंगे मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय सचिव प्रवीण मणि त्रिपाठी लखनऊ मीडिया प्रभारी अनुपम भदौरिया जिला उपाध्यक्ष नितिन सचान राजाजीपुरम अध्यक्ष रवि दुबे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मवीर सिंह कोषाध्यक्ष सनत कुमार शुक्ला ट्रांसपोर्ट नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता मोहान रोड कोषाध्यक्ष करुणेश प्रताप सिंह उपाध्यक्ष रामजी शुक्ला युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष नमन बाजपेई राजू अरोड़ा मंत्री पिंटू सोनकर बाल बिहारी मिश्रा निक्कू निगम राज तिवारी अभिषेक सोनकर रवि कुमार के कृष्णानी अवनीश गौतम महेश सिंह देवेश कृष्णानी योगेश कुमार शुक्ला देवेंद्र मिश्रा दिनेश राठौरआदि व्यापरीगण उपस्थित रहे प्रवीण मणि त्रिपाठी ने व्यापारियों से बात करते हुए कहा संगठन का पूरा प्रयास रहेगा जो समस्या व्यापारियों द्वारा बताई गई है उसका समाधान कराने के लिए शासन प्रशासन से मिलकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी वहीं दूसरी तरफ पता चला कि राजाजीपुरम इकाई अध्यक्ष रवि दुबे जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया है सभी व्यापारी रवि दुबे के घर पहुंच कर ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी माता जी की आत्मा को शांति दे परिवार को दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें

## भारतीय किसान संघ ने 4 सूत्रीय ज्ञापन S.D.M को सौपा

**लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा**

**हसनपुर** : शनिवार को भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने तहसील दिवस में किसानों की समस्याओं को लेकर चार सूत्रीय ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री के नाम संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी हसनपुर को सौंपा,जिसमें मांग की गई कि किसानों को सिंचाई हेतु चौदह घंटे लगातार बिजली आपूर्ति की जाए, जिले से गुजर रही मध्य गंगा नहर में जल्द पानी छोड़ा जाए जिससे वाटर लेवल बढ़ सके, नहरों और नदियों में स्नान के दौरान प्रशासन की लापरवाही से जनहानि को शीघ्र रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाए, ग्राम भदौरा में किसान रामचंद्र शर्मा के खेत की ठियाबनदी होने के बाबजूद भी राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण चिन्हित खेत की मैड नहीं बनाई गई है जिसे जल्द पूरा कराया जाए, हसनपुर से भदौरा ओर उधनपुर से मुंसिफ कोर्ट तक जाने वाला मार्ग बहुत ही खराब स्थिति में है जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है परेशानियों के समाधान हेतु जल्द ठीक कराया जाए, इस अवसर पर प्रांतीय गन्ना प्रमुख महीपाल सिंह, जिला अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष धर्मपाल सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, ब्लॉक सहमंत्री जगदीश सिंह, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कोविंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह, रुमाल सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

## विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने ग्राम चौपाल का किया शुभारंभ; ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण

**लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा**

**मुरादाबाद।** आज कुंदरकी विधानसभा के मुंडापांडे विकास खंड के ग्राम भदासना एवं भायपुर में शासन द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कराया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना था। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने फीता काटकर ग्राम चौपाल का शुभारंभ किया।कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन, फॉर्मर रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, विद्युत और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। अपने संबोधन में ठाकुर रामवीर सिंह ने आगे कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गांव, गरीब, किसान, महिला, वृद्ध और दिव्यांग तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्राम चौपाल जैसे कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं, जिससे समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर ही संभव हो पाता है। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि सभी प्राप्त प्रकरणों का तत्काल परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण किया जाए। साथ ही, की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट मेरे कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके। ग्राम चौपाल में विभिन्न विभागों के स्टाल लगे थे, जिन पर सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने पर संतोष व्यक्त किया और इस पहल की सराहना की। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन की भावना के अनुरूप है।

## श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन भगवान वामन अवतार और राजा बलि का प्रसंग सुनाया गया

**लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा**

**हसनपुरः** शनिवार को नगर के झारखंड महादेव शिवाला मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा वृंदावन धाम से पधारी कथा वाचिक पूज्या सिद्धि पूनम जी श्रीधाम वृंदावन के श्री मुख से की गई, कथा वाचिका सिद्धि पूनम जी ने प्रथम दिन भागवत महापुराण के महत्व की कथा, ज्ञान भक्ति बैराग की कथा, गोकर्ण कार्य तथा साप्ताहिक यज्ञ तथा श्रवण की विधि का रसपान कराया वहीं उन्होंने भगवान वामन अवतार एवं राजा बलि का प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए, कथा वाचिका ने बताया कि जब देवताओं का ऐश्वर्या छिन गया तब भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया छोटे से ब्राह्मण बटुक हाथ में कमंडल छत्र और जनेऊ धारण किया जब राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो उनकी आभा देखकर राजा बलि स्वयं उनके चरणों में झुक गए जहां राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भाप लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि छल करने आए स्वयं नारायण है उन्होंने बलि को दान देने से रोका लेकिन राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव यदि देने वाला नारायण है और लेने वाला भी नारायण है तो यह छल नहीं मुझ पर उनकी असीम कृपा है इसी बीच भगवान वामन ने राजा बलि से कुछ मांगने की इच्छा जताते हुए कहा तो राजा बलि ने कहा जो चाहे मांग लो मैं आपको अवश्य दूंगा इस बीच भगवान वामन ने तीन पग पृथ्वी मांग ली राजा बलि ने उन्हें देने का वादा कर दिया जहां भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली दूसरे पग में समस्त आकाश सर्ग नाप लिया, अब बलि का सब कुछ भगवान का हो चुका था भगवान ने राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहां रखूं तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो गया राजा बलि ने विनम्रता से कहा की आप तीसरा पग प्रभु मेरे मस्तक पर रख दो इस समर्पण को सुनकर पंडाल में बैठी श्रद्धालु माताएं बहने भावुक हो गई क्योंकि यह प्रसंग है कि अहंकार को प्रभु के चरणों में झुका देना ही सबसे बड़ा दान है उधर बली की इस निश्चल भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया और स्वयं उनके पहरेदार यानी द्वारपाल बन गए, सिद्धि पूनम जी ने अंत में समझाया कि जो भगवान को अपना सब कुछ सौंप देता है भगवान स्वयं उसके अधीन हो जाते हैं इधर कथा के दौरान जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव के नारे से पंडाल गुज उठा इस बीच कथा समाप्ति के उपरांत आरती हुई तथा प्रसाद का वितरण भी किया गया, इस मौके पर संदीप अग्रवाल, पुनीत अग्रवाल, गिरजा शंकर अग्रवाल आदि सहित भारी संख्या में महिला श्रद्धालु गण मौजूद रही ।

## संक्षिप्त समाचार

### वैशाली में जंदाहा थानाध्यक्ष सस्पेंड, मनोज कुमार पर शराब माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगे

**लोकतंत्र की शान : हाजीपुर।** वैशाली जिले में पुलिस प्रशासन ने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जंदाहा थाना के थानाध्यक्ष मनोज कुमार को शराब माफियाओं को संरक्षण देने के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई वैशाली पुलिस द्वारा की गई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मनोज कुमार पर लंबे समय से शराब कारोबारियों के साथ मिलीभगत के आरोप लग रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विभागीय जांच बिठाई गई थी। इस जांच में प्रथम दृष्टया थानाध्यक्ष की शराब माफियाओं के साथ सांठगांठ और उन्हें संरक्षण देने की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर, जिला पुलिस प्रशासन ने उन्हें सेवा से निलंबित करने का कड़ा निर्णय लिया है।

### सांसद के करीबी से 1 लाख की फिरौती, व्हाट्सएप पर धमकी, कहा- पैसे दिए तो 10 साल तक सुरक्षित रहोगे

**लोकतंत्र की शान : हाजीपुर।** बिहार के वैशाली जिले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के करीबी और हाजीपुर के आदर्श इमरजेंसी हॉस्पिटल के निदेशक मनीष कुमार उर्फ पिंटू यादव से एक लाख रुपये की फिरौती मांगी गई है। अपराधियों ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए यह धमकी दी है कि अगर रकम नहीं दी गई तो गोली मार दी जाएगी। अपराधियों ने कोड वर्ड में "1L दो" लिखकर फिरौती की मांग की। मैसेज में यह भी कहा गया है कि अगर रकम दे दी गई तो अगले दस साल तक कोई परेशानी नहीं होगी। समय पर भुगतान न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। पिंटू यादव ने बताया कि उन्हें यह धमकी भरा मैसेज रात को सोने जाने से पहले मोबाइल पर मिला। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और अधिकारियों से न्याय की मांग की है। इस घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारिक समुदाय में चिंता का माहौल है। पीड़ित ने स्थानीय थाने और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी है। पुलिस अब मैसेज भेजने वाले नंबर को ट्रैक करने और अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस ने पिंटू यादव को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का आश्वासन भी दिया है। मनीष कुमार उर्फ पिंटू यादव को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का करीबी नेता माना जाता है। वह पूर्व में उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

### बालू अनलोड करते हाइवा पलटा, बाइक सवार की मौत लोगों ने हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग को जाम किया

**लोकतंत्र की शान : हाजीपुर।** वैशाली जिले के हाजीपुर में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग पर सुल्तानपुर के पास हुई, जहां बालू से लदा एक हाइवा अनलोडिंग के दौरान पलट गया। मृतक की पहचान गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी वीरचंद चौधरी (पिता स्व. रविंद चौधरी) के रूप में हुई है। वीरचंद चौधरी बाइक से काम पर जा रहे थे। तभी सड़क किनारे बालू अनलोड कर रहा एक हाइवा अनियंत्रित होकर पलट गया। हाइवा की चपेट में आने से वीरचंद चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक वीरचंद चौधरी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। इस हादसे के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलते ही गंगा ब्रिज थाने और हाजीपुर औद्योगिक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। औद्योगिक थाने की पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुर्घटनाग्रस्त हाइवा अभी भी सड़क पर पड़ा हुआ है।

### एस्कॉर्ट गाड़ी से टकराई महिला आयोग की अध्यक्ष की कार, बाइक सवार को बचाने में हादसा

**लोकतंत्र की शान : हाजीपुर।** हाजीपुर-मुजफ्फरपुर नेशनल हाई-वे पर शुक्रवार को बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें कंधे में चोट आई है। बॉडी गार्ड भी घायल है। अप्सरा मिश्रा ने बताया, हम केस की सुनवाई कर के लौट रहे थे। सड़क पर एक युवक पड़ा था। उसे बचाने के चक्कर में एस्कॉर्ट की गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया। ठीक पीछे चल रही मेरी गाड़ी एस्कॉर्ट गाड़ी में टकरा गई। जिस जगह ये हादसा हुआ वहां एक युवक का शव भी मिला है। मृतक की पहचान मेरठ के त्रिलोकी मौर्य के बेटे सुरेश मौर्य के रूप में हुई है। सुरेश हाजीपुर के दिग्गी पचकुरवा में किराए के मकान में रहता था और रामाशीष चौक स्थित एक गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। हादसा महुआ मोड़ के पास हुआ। हादसा कैसे हुआ पुलिस इसकी जांच कर रही है। हादसे के वक्त गाड़ी में अप्सरा मिश्रा के साथ उनके पति डॉ. रणधीर भी मौजूद थे। उन्होंने भास्कर को बताया, एक केस की सुनवाई के लिए वो बेगूसराय गई थीं। वहां से पीड़िता के पति को लेकर मुजफ्फरपुर पीड़िता के मायके गई थीं। मामला सुलझाकर वापस पटना लौट रही थीं। तभी शाम को करीब 7:30 बजे हाजीपुर में उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी एस्कॉर्ट के आगे एक बाइक सवार काफी स्पीड में था। डिवाइडर से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो गया। पीछे उनकी गाड़ी थी। सभी गाड़ियां काफी स्पीड में होने के कारण उनकी गाड़ी अपनी ही एस्कॉर्ट की गाड़ी से टकरा गई। उन्हें कंधे और बाजू में हल्की छोटे आई हैं। तब गाड़ी में 4 लोग सवार थे। उनके गार्ड को छाती में चोट आई है। स्थानीय लोगों ने बताया, टक्कर मारने के बावजूद, न तो एस्कॉर्ट गाड़ी रुकी और न ही काफिले का कोई अन्य वाहन। सभी गाड़ियां तेज रफ्तार से पटना की ओर निकल गईं। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुरेश मौर्य को मृत घोषित कर दिया।

### प्रेम-प्रसंग में विधवा की गला रेतकर हत्या, वैशाली में 4 साल पहले पति की मौत, पड़ोसी से चल रहा था अफेयर

**लोकतंत्र की शान : हाजीपुर।** हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते विधवा महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की रात आरोपी ने महिला को अपने साथ चलने को कहा। लेकिन जब उसके साथ जाने से मना किया तो वो नाराज हो गया। वो जबरदस्ती उसे घर से बाहर ले गया और करीब 500 मीटर दूर चाकू से महिला के गला और पेट पर वार कर फरार हो गया। परिजन ने घायल महिला को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना मगरहट्टा पोखर के पास देर शाम हुई। मृतका की पहचान हेला बाजार निवासी स्वर्गीय सकलदीप पासवान की पत्नी हेमंती देवी(32) के रूप में हुई है। उसके पति की चार साल पहले मौत हो गई थी। मृतका के चार बच्चे हैं, 2 बेटा और 2 बेटी। पति के मौत के बाद महिला आसपास के घरों में बर्तन धोकर अपना परिवार को चलाती थी। दरअसल, पति के मौत के बाद हेमंती का इंदल पासवान से संपर्क हुआ। कुछ दिन बाद ही पूरे गांव में दोनों के प्रेम-प्रसंग की बात फैल गई। हालांकि गांव के लोग इस संबंध का विरोध करते थे। उनका कहना था कि सारे बच्चे अब बड़े हो गए है। तुम यह सब छोड़ दो, बच्चो पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन महिला ने गांव समाज की बात को नकार दिया था। इस संबंध में मृतका के पड़ोसी रामबाबू पासवान ने बताया कि इंदल पासवान ने महिला के पेट और गले पर चाकू से वार कर हत्या की है। इंदल को मना करते थे, उसके बावजूद वो लोग नहीं माने। प्रेम-प्रसंग का विरोध करने पर इंदल पासवान कई बार मारपीट भी किया था। हेमंती की बेटी बड़ी हो गई थी। वो जब भी मां को मना करती थी, तो वो नहीं बात करने की बात कहकर उसे डांट देती थी। रामबाबू पासवान ने बताया कि देर शाम इंदल पासवान हेमंती को घर से बुलाने आया था। महिला नहीं जा रही थी फिर भी वो महिला को घर से जबरन बुलाकर ले गया। इसके बाद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही वैशाली पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग, एसडीपीओ सदर-1 सुबोध कुमार और नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाना शुरू किया। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त की पहचान उसी मोहल्ले के इंदल पासवान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, मृतका और अभियुक्त को घटना से पहले अक्सर साथ आते-जाते देखा गया था। प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। पुलिस आरोपी इंदल पासवान की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी ने यह भी जानकारी दी कि क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

# विश्वकर्मा समाज की एकजुटता से ही राजनीतिक अधिकार संभवः महेंद्र शर्मा

लोकतंत्र की शान

**सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसाः** शहर के सम्राट अशोक भवन में विश्वकर्मा शक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित विश्वकर्मा सम्मान समारोह में समाज की एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी को लेकर जोरदार संदेश दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। समारोह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं की भागीदारी रही, जिससे पूरा आयोजन विश्वकर्मा कुंभ जैसा नजर आया। कार्यक्रम में बढ़ई, लोहार, कुम्हार, ठठेरा और सोनार समाज के लोगों ने एकजुटता का संकल्प लिया तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए कोसी प्रमंडल स्तर पर विशाल रैली और सभा आयोजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत में वासुदेव शर्मा और संजय स्वर्णकार के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद समारोह की अध्यक्षता कर रहे विश्वकर्मा शक्ति मोर्चा के अध्यक्ष एवं लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि जब तक समाज जागरूक और सजग नहीं होगा, तब तक राजनीतिक रूप से मजबूत भागीदारी संभव नहीं है। उन्होंने सभी से एकजुट होकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कार्य करने का आह्वान किया। कोसी प्रमंडलीय स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष रामसुंदर साहा ने कहा कि भले ही पेशे अलग-अलग हों, लेकिन सभी विश्वकर्मा के वंशज हैं और अपने अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष जरूरी है। वहीं, प्रजापति संघ के जिलाध्यक्ष रामोतार पंडित ने समाज में चट्टानी एकता स्थापित करने पर जोर दिया। समारोह के दौरान पंचायत जनप्रतिनिधियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में ठठेरा संघ के जिलाध्यक्ष धनिकलाल ठठेरा, स्वर्णकार संघ के शशि सोनी, इंजीनियर रामेश्वर ठाकुर, इंजीनियर मिथिलेश भारती, पूर्व विधायक प्रत्याशी पिंटू शर्मा, डॉ. के.डी. शर्मा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि चंद्रदेव कुमार, पूर्व वार्ड पार्षद सरोजनी देवी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के अध्यक्ष डॉ. रघुनंदन शर्मा, डॉ. संजय कुमार शर्मा, सब-इंस्पेक्टर विष्णु कुमार, इंजीनियर संतोष कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों और हजारों की संख्या में लोगों की भागीदारी रही। समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने और समाज को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

# लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

लोकतंत्र की शान

**सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसाः** प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा श्री राजेश कुमार (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में शनिवार को प्रमंडल स्तरीय समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति एवं लंबित मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने ग्रामीण कार्य विभाग सहित अन्य तकनीकी विभागों को निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाई जाए तथा लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य निष्पादन पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके पश्चात प्रमंडल अंतर्गत संबंधित जिलों के स्थापना उप समाहर्ता, संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के साथ आयोजित बैठक में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित विभागीय अभिलेखों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान पाया गया कि कई मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। प्रमंडलीय आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि नौ माह से अधिक समय से लंबित विभागीय मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर नियमित सुनवाई करते हुए शीघ्र अंतिम रूप से निष्पादित किया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अनुपालन प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा और कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

# 'कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ाना जजिया टैक्स से भी क्रूर'

लोकतंत्र की शान, पटना

**कांग्रेस बोली- मोदी जी पकौड़ा तलो बोलते हैं, फिर सिलेंडर के दाम भी बढ़ाते हैं**

कांग्रेस ने मोदी सरकार के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के फैसले को जजिया टैक्स से भी ज्यादा क्रूर बताया है। कल ही कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पकौड़ा तलो योजना के पैरोकार हैं। वह पकौड़ा कमर्शियल सिलेंडर पर ही तला जाता है। उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर का दाम सीधे 1000 रुपए तक बढ़ा दिया।'

असित नाथ तिवारी ने कहा कि, 'मामूली ठेले पर भी चाय पीने जाएंगे तो अब 20 रुपए की चाय मिलेगी। छोटा सिलेंडर, जिसमें 5kg गैस आता हैं, उसकी कीमत अब पौने 300 रुपए तक बढ़ा गई है। मोदी जी काफी जुल्म किया है। देश इसका जवाब देगा।' कॉमर्शियल सिलेंडर 1 मई से 994 रुपए तक महंगा हो गया है। 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर की कीमतों में 261 रुपए का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 'छोटू' सिलेंडर की रिफिल कीमत 813.50 रुपए हो गई है। इसके अलावा 'ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026' प्रभावी हो गए हैं।

# जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए 'सहयोग शिविर' का आयोजन, 19 मई को पंचायत स्तर पर लगेगा शिविर

लोकतंत्र की शान

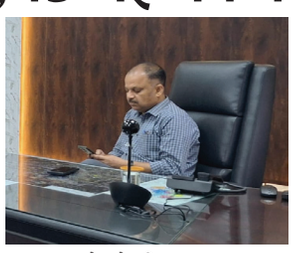

**सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसाः** जन शिकायतों के सरल एवं प्रभावी निवारण के उद्देश्य से जिला प्रशासन सहरसा द्वारा पंचायत स्तर पर "सहयोग शिविर" आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। समाहरणालय, सहरसा द्वारा जारी संयुक्त आदेश (पत्रांक-666, दिनांक 01 मई 2026) के अनुसार यह शिविर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। प्राप्त निर्देश के अनुसार, मई माह के तृतीय मंगलवार यानी 19 मई 2026 को जिले के विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता अथवा समकक्ष पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। शिविर का आयोजन पंचायत सरकार भवन या उसके निकट किसी सार्वजनिक स्थल पर सुबह 10:00 बजे से किया जाएगा। इस शिविर में आम नागरिकों से आवेदन एवं शिकायतें प्राप्त कर उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने के लिए नामित कर्मी 02 मई 2026 से ही आयोजन स्थल पर उपस्थित रहेंगे और प्राप्त आवेदनों का पंजी संधारण किया जाएगा। साथ ही, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए कार्रवाई कराई जाएगी तथा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर के दौरान सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी अपने-अपने स्तर से मामलों का निष्पादन करेंगे। नौ माह से अधिक लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, सभी प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों को पंजीकृत कर "शिविर संवाद समाधान पोर्टल" के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सभी थानाध्यक्ष संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर शिविर में विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक सहयोग देंगे और शिविर के दिन स्वयं उपस्थित रहेंगे। वहीं, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी को शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार मीडिया के माध्यम से कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों के माध्यम से आम जनता तक शिविर की सूचना पहुंचाएं तथा आयोजन स्थल पर बैठने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। शिविर में उपस्थित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने न्यायालयों में लंबित एवं निष्पादित मामलों की सूची का प्रदर्शन भी किया जाएगा, ताकि आम लोगों को मामलों की जानकारी सुलभ हो सके। साथ ही, केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी शिविर में उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर समाप्ति के बाद संबंधित पदाधिकारी द्वारा एक संक्षिप्त प्रतिवेदन वरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें निष्पादन की स्थिति एवं लापरवाही बरतने वाले कर्मियों की जानकारी भी शामिल होगी। जिला स्तर पर इन शिविरों की निगरानी जिला जन शिकायत कार्यालय, सहरसा द्वारा की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

# पुलिस ने 8 अंतरराज्यीय तस्करों को पकड़ा, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना के नदी थाना पुलिस ने नशीली दवाओं के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अंतरजिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया है।

**गश्ती के दौरान कच्ची दरगाह में पकड़े गए संदिग्धः** शुक्रवार को थानाध्यक्ष सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में पुलिस टीम वाहन जांच और फरार अपराधियों की तलाश में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कच्ची दरगाह के पास पीपा पुल की ओर से आ रहे 6 पुरुष और 2 महिलाएं संदिग्ध अवस्था में दिखे। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया।

**बैग से निकली 675 बोतल नशीली दवाः** तलाशी के दौरान आरोपियों के बैग और थैलों से 675 बोतल (67.5 लीटर) 'कोडीन फॉस्फेट' युक्त कफ सिरप और 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए गए। जब्त सिरप की कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जा रही है।

**वैशाली के रहने वाले आरोपीः** गिरफ्तार आरोपियों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इनकी पहचान वैशाली जिले के विभिन्न इलाकों के रहने वाले प्रमेंट राय, रंजीत कुमार, संजीव कुमार, लाला राय, विरथ राय, नितिश राय, रिंकु देवी और हाजीपुर की सुमन कुमारी के रूप में हुई है।

**NDPS एक्ट के तहत केस दर्जः** फतुहा एसडीपीओ-1 अवधेश कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले में कांड संख्या 167/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

**तस्करी नेटवर्क की जांच तेजः** पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। आशंका है कि यह नशीली दवाओं की सप्लाई बड़े स्तर पर करता था। इस कार्रवाई में एसआई देवकर्ण बंटी, विवेक कुमार, एएसआई संतोष कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही।

# पीएमसीएच के डॉक्टर 600 परिवारों को लेंगे गोद, 3 साल तक देंगे फ्री इलाज

लोकतंत्र की शान, पटना

**फुलवारी में 'फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम' शुरू**

केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट 'फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम' का शनिवार को फुलवारी शरीफ के इस्माइलपुर ढ़िबरा पंचायत में शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सीनियर और जूनियर डॉक्टर ग्रामीण परिवारों को गोद लेकर उन्हें नियमित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री श्याम रजक ने किया। इस मौके पर उन्होंने इसे समाज के कमजोर वर्ग तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

**100 MBBS छात्रों की टीम करेगी सर्वेः** PMCH की डॉक्टर निशिता ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना है। इसके लिए करीब 100 MBBS छात्रों की टीम बनाई गई है, जो गांव-गांव जाकर घर-घर सर्वे करेगी। सर्वे के दौरान परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी बीमारियों और आवश्यक इलाज का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत MBBS छात्र करीब 600 परिवारों को गोद लेंगे और तीन वर्षों तक उनकी स्वास्थ्य निगरानी करेंगे। प्रत्येक छात्र 3 से 5 परिवारों की जिम्मेदारी संभालेगा। कार्यक्रम के दौरान परिवार के सदस्यों की नियमित जांच, बीमारी की पहचान और आवश्यक उपचार के साथ उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इसके अलावा समय-समय पर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच और परामर्श की सुविधा दी जाएगी। विधायक श्याम रजक ने कहा कि, उनका लक्ष्य 'स्वस्थ फुलवारी, स्वच्छ फुलवारी, शिक्षित फुलवारी' बनाना है। उन्होंने कहा, 'स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। जब मेडिकल छात्र सीधे परिवारों से जुड़ेंगे, तो बीमारियों की समय पर पहचान होगी और जागरूकता बढ़ेगी।' उन्होंने कहा कि, यह पहल 'सबका स्वास्थ्य, सबका विकास' की सोच को जमीन पर उतारने का सशक्त माध्यम साबित होगी।

# भागलपुर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण का पार्थिव शरीर सदाकत आश्रम पहुंचा

लोकतंत्र की शान, पटना

भागलपपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा का पार्थिव शरीब शनिवार को पटना के सदाकत आश्रम लाया गया है। अमर रहे के नारे कांग्रेसी लगाते रहे। पार्थिव शरीर को पार्टी के झंडे से लपेटा गया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम रोने लगे। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। भागलपुर में शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी।

वे दिल्ली से पटना कार से लौट रहे थे। इसी दौरान यूपी के कन्नौज में ड्राइवर को झपकी आने उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा की सड़क हादसे में मौत पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा जी के सड़क दुर्घटना में हुए असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।' उन्होंने आगे लिखा, 'संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। शोक संतप्त परिजनों, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हूं।'

# 'अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं होगा'

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना के JDU ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने अल्पसंख्यक समाज को एकजुट रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि, 'वर्तमान सरकार सबको साथ लेकर चलने के सिद्धांत पर काम कर रही है। किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होगा।' डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसका रास्ता पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा तय किया गया है। उन्होंने कहा कि, 'सरकार उसी नीति और सिद्धांतों का पालन कर रही है, जो पहले से स्थापित हैं।'

**3C नीति पर कोई समझौता नहीं- विजय चौधरीः** डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने बताया कि, 'मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि 3C (क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म) पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि, 'सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर नीतीश कुमार की जो नीति रही है, वही आगे भी जारी रहेगी।

**विपक्ष पर माहौल बनाने का आरोपः** विजय चौधरी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि, 'पहले की सरकारों में केवल माहौल बनाया जाता था, खासकर अल्पसंख्यक समाज को लेकर।' उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि, 'एनडीए सरकार से पहले अल्पसंख्यकों के लिए ठोस काम नहीं हुए।'

**CAA और वक्फ कानून पर बोले डिप्टी सीएमः** डिप्टी सीएम ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और वक्फ संशोधन कानून का जिक्र करते हुए कहा कि, 'इन मुद्दों पर देशभर में बेवजह हंगामा किया गया। आठ साल में किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं छीनी गई है। इन मुद्दों पर लोगों को भ्रमित किया गया।'

**मतदाता सूची और SIR पर दी सफाईः** डिप्टी सीएम ने कहा कि, 'SIR को लेकर भी यह भ्रम फैलाया गया कि अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह अल्पसंख्यक समाज को गुमराह कर रहा है।'

मुख्यमंत्री के जनता दरबार में टोपी नहीं पहनने के सवाल पर विजय चौधरी ने हल्के अंदाज में कहा कि 'अगर टोपी से सरकार का प्रदर्शन मापा जाता है तो हमें 2-4 टोपी पहना दीजिए।' उन्होंने कहा कि, 'सरकार का काम, उसके प्रदर्शन से आंका जाना चाहिए।'

## संक्षिप्त समाचार

### नारनौल रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की मांग,स्टेशन अधीक्षक से मिले यात्री

**लोकतंत्र की शान : नारनौल।** नारनौल में दैनिक रेल यात्री एवं जन कल्याण संघ ने यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर शनिवार को स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक जयपुर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की प्रतिलिपि मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल अभियंता और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। संघ के अध्यक्ष गणेश शर्मा ने बताया कि नारनौल रेलवे स्टेशन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और व्यस्त स्टेशन है, जहां प्रतिदिन हजारों यात्री आवागमन करते हैं। इसके बावजूद यहां सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्टेशन परिसर में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म संख्या एक से प्लेटफॉर्म संख्या दो तक सुरक्षित और सुगम फुटपाथ (वॉकवे) निर्माण की आवश्यकता भी जताई गई, ताकि बुजुर्ग, दिव्यांगजन और रेलवे कर्मचारी आसानी से आवागमन कर सकें। संघ ने वर्तमान फुटओवर ब्रिज की खड़ी सीढ़ियों को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि इन सीढ़ियों के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को भारी दिक्कत होती है। इसलिए इसे रैंपयुक्त और दिव्यांगजन के अनुकूल बनाए जाने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म संख्या दो पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था न होने का मुद्दा भी उठाया गया। संघ पदाधिकारियों ने मांग की कि यहां पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यात्री शेड के विस्तार की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई। पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान शेड यात्रियों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, जिससे धूप और बारिश के दौरान यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस मौके पर अनेक दैनिक यात्री मौजूद रहे।

### कर्मचारियों की हड़ताल से फतेहाबाद में लगे कचरे के ढेर

**लोकतंत्र की शान : फतेहाबाद।** नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर फतेहाबाद नगर परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल में सफाई कर्मचारियों के अलावा ऑफिस स्टाफ ने भी भाग लिया। कर्मचारियों के इस सामूहिक कार्य बहिष्कार के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सडक़ों के किनारे और गली-मोहल्लों में कूड़े के ऊंचे-ऊंचे ढेर लग गए हैं, जिससे शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते शनिवार को भी डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाली गाडिय़ां नहीं चलीं। इस कारण घरों में कचरा जमा हो गया और लोगों ने मजबूरी में कचरा सडक़ों पर फेंकना शुरू कर दिया है। नगर परिषद कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा रहा, जिससे जनता से जुड़े प्रशासनिक कार्य पूरी तरह ठप्प रहे। शनिवार सुबह कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता इकाई प्रधान नरेश राणा, जिला प्रधान विजय ढाका व सचिव वीरू रत्ति ने संयुक्त रूप से की। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को लगातार अनसुना कर रही है। समान काम-समान वेतन के मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आने के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला, तो इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। कर्मचारियों ने मांग की है कि ठेका प्रथा को समाप्त कर सभी विभागों में पक्की भर्ती की जाए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये तय हो। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। फरीदाबाद अग्निकांड के शहीद कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद व नौकरी मिले।

### सरकारी स्कूल में पानी पीने के बाद 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

**लोकतंत्र की शान : बाड़मेर।** जिले के सनावड़ा मेघवालों की बस्ती स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब पानी पीने के बाद 13 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के शरीर पर खुजली शुरू हो गई और जगह-जगह लाल निशान बनने लगे। स्थिति गंभीर होते देख स्कूल प्रशासन ने तत्काल सभी बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार शनिवार को स्कूल में 'नो बैग डे' आयोजित किया गया था और छात्र-छात्राएं सामान्य गतिविधियों में शामिल थे। लंच से पहले अचानक एक बच्ची को तेज खुजली होने लगी, जिसके बाद उसके शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। स्कूल स्टाफ ने तुरंत परिजनों को सूचना देकर बच्ची को अस्पताल भिजवाया, लेकिन कुछ ही देर में तीन से चार अन्य बच्चों में भी इसी प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे।देखते ही देखते करीब 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सभी बच्चों को पहले सनावड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाड़मेर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस के इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन के अनुसार शनिवार सुबह बच्चों की हालत अचानक खराब हुई थी। बच्चों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि पानी पीने के बाद उन्होंने स्कूल के बाहर बिकने वाली 'चुस्की' भी खाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया। एडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत सहित शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे तथा बच्चों की स्थिति का जायजा लिया।जिला शिक्षा अधिकारी देवाराम चौधरी ने बताया कि बच्चे घर से भोजन करके स्कूल आए थे। स्कूल में मिड-डे मील (पोषाहार) तैयार हो रहा था, लेकिन बच्चों की तबीयत उसके सेवन से पहले ही बिगड़ गई थी। ऐसे में फिलहाल पानी या बाहर खाई गई चुस्की को संभावित कारण मानते हुए जांच की जा रही है। बाड़मेर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. हनुमान चौधरी ने बताया कि सभी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पानी के स्रोत और बच्चों द्वारा खाई गई चुस्की के नमूनों की जांच कराई जा सकती है, ताकि बीमारी के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

### जींद में 2931 विद्यार्थी देंगे नीट की परीक्षा,तैयारियां पूरी

**लोकतंत्र की शान : जींद।** जिला प्रशासन ने रविवार को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को लेकर जिला में कुछ छह परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा दोपहर दो बजे शुरू होगी और पांच बजकर 20 मिनट पर खत्म होगी। परीक्षार्थी को आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। जहां 2931 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। रीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसी टीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन तथा अन्य आवश्यक तकनीकी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। परीक्षा शांतिपूर्णए निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आसपास फोटो स्टेट की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है। परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंचना बेहद जरूरी है। क्योंकि बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन सहित अन्य प्रक्रियाएं समय पर पूरी करनी होंगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र ही लेकर जा सकेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गैजेट या अन्य प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टि से एक निरीक्षक व तीन महिला पुलिस कर्मियों सहित कुल 21 पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। वहीं पांच प्रमुख लोकेशनों पर तीन उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी निगरानी एवं समन्वय के लिए नियुक्त किए गए हैंए जो पूरे सिस्टम पर सतत नजर बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त, जिले में पांच पेट्रोलिंग पार्टियां गठित की गई हैं। जिनमें प्रत्येक पार्टी में चार पुलिसकर्मी एवं दो असलाहधारी जवान शामिल हैं।

# पुलिस अधीक्षक ने जन चौपाल में दो कुपोषित बच्चों को लिया गोद

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

**सीधी।** मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित जिला सीधी के दुरुस्त सुदूर अंचल ग्राम रुद्रा भदौरा के करौदी गांव स्थित आंगनबाड़ी परिसर में आयोजित जन चौपाल में पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी भापुसे ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा उन्हें उनके अधिकारों एवं शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक किया। बैगा समाज के बाहुल्य क्षेत्र में जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं उसके संशोधित प्रावधान 2016 के बारे में जागरूकता फैलाना, साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताना, नशामुक्ति के महत्व एवं नशा सेवन के दुष्परिणामों के प्रति सचेत करना तथा महिला संबंधी अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी श्रीमती माया गोस्वामी द्वारा विभागीय योजनाओं, विशेषकर बाल आशीर्वाद योजना की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी कुसमी अरुणा द्विवेदी ने महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों तथा साइबर सुरक्षा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में गुड टच एवं बैड टच की जानकारी भी सरल एवं प्रभावी तरीके से दी गई। जन चौपाल के दौरान ग्राम में दो बच्चों के कुपोषित होने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए निर्मला बैगा उम्र 2 वर्ष 8 माह एवं आकाश बैगा उम्र 2 वर्ष 3 माह को उनके पूर्ण पोषण तक गोद लेने की घोषणा की। इस पहल ने पुलिस की जनसेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए ग्रामीणों में विश्वास और सकारात्मकता को और सुदृढ़ किया। इस अवसर पर एससी/एसटी वर्ग के नागरिकों को उनके अधिकारों, कानूनी संरक्षण एवं राहत प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया जन चौपाल के दौरान पेसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई, जो अनुसूचित क्षेत्रों आदिवासी बहुल इलाकों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने एवं स्थानीय संसाधनों पर उनके अधिकार सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून है। साइबर जागरूकता के तहत बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या लुभावने ऑफर के झांसे में आकर बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। जन चौपाल में पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी, थाना प्रभारी कुसमी अरुणा द्विवेदी, महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी माया गोस्वामी, पर्यवेक्षक मान कुमारी, थाना स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं लगभग 250 ग्रामीणजन उपस्थित रहे। उपस्थित ग्रामीणजनों को पुलिस अधीक्षक द्वारा फल, मिस्ठान एवं चॉकलेट इत्यादि के वितरण किया गया।

## आरटीआई का आदेश सीएससी में बेअसर

### बीएमओ के निर्देश पर भी नहीं भेजी जा रही जानकारी

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

**सीधी।** शासन का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन में पूरी तरह से बेअसर नजर आ रहा है। तत्संबंध में नगर परिषद रामपुर नैकिन वार्ड क्रमांक 11 निवासी राजेन्द्र मिश्रा ने बताया कि उनके द्वारा सूचना के अधिकार 2005 के तहत दिनांक 20 मार्च 2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन में दो वित्तीय वर्षों के मदवार आय-व्यय व्यौरे की जानकारी चाही गई थी। इसके संबंध में कार्यालय द्वारा पत्र भेजकर कहा गया कि जानकारियां लगभग 32 हजार पेज की होने एवं दो रुपए प्रति पन्ने की फोटोकांपी हेतु 64 हजार रुपए जमा किया गया। जिस पर प्रार्थी के द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त वांछित जानकारियां प्रार्थी के मेल पर प्रेषित कर दिया जाए। फिर भी आवश्यक जानकारी देने में लगातार हीलाहवाली की जा रही है। उनके द्वारा कैशबुक की समस्त मद की छांयाप्रति, स्टॉक स्टोर, आशा कार्यकर्ता भुगतान, प्रसूति सहायता प्रोत्साहन, आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय भुगतान को छोंडक़र शेष समस्त खरीद-फरोख्त, आय-व्यय, समस्त रोगी कल्याण निधि मद सहित जानकारियां मांगी गई हैं। मांगी गई जानकारी देने के लिए बीएमओ रामपुर नैकिन द्वारा बीएएम को दो बार लिखित पत्र भी जारी किया गया फिर भी जानकारी देने में लगातार हीलाहवाली की जा रही है।

# अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर श्रमिक सम्मान का संदेश

लोकतंत्र की शान

**(बरेली संदीप चंद्रा उत्तर प्रदेश )** बरेली की पूर्व महापौर श्रीमती सुप्रिया जी ने आज अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर मंडल उत्तर प्रदेश के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर ख्यात फिल्मी कलाकार एवं बुद्धिजीवी श्री रज़ा मुराद सहित अनेक समाजसेवी एवं प्रमुख जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्रीमती सुप्रिया जी ने श्रमिकों के सम्मान, उनके अधिकारों की रक्षा तथा सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिक चाहे खेत-खलिहानों में कार्यरत हों, उद्योगों एवं कारखानों में, अथवा किसी अन्य क्षेत्र में—समाज और राष्ट्र के विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। ऐसे में उन्हें उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने श्रमिक हितों की रक्षा हेतु निरंतर संघर्ष, सकारात्मक पहल एवं जन-जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि श्रमिकों की भागीदारी को सशक्त किए बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना अधूरी है।

# किरतपुर के युवक की कश्मीर में नृशंस हत्या, गांव में पसरा मातम

**» रोज़गार के लिए गया था युवक, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़**

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

**किरतपुर/बिजनौर।** जनपद बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती निवासी 35 वर्षीय साजिद पुत्र मुस्ताक की कश्मीर में नृशंस हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि साजिद रोज़गार के सिलसिले में कश्मीर गया हुआ था और वहीं रहकर काम कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात परिस्थितियों में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक का शव मिलने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। सूत्रों के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र के लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचने लगे। जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

**न्याय की मांगः** पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है।

# मनमानी कार्यों के जरिए ठिकाने लगाई जा रही लघु बनोपज फंड की राशि

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

**» संचालक मंडल द्वारा नहीं किया गया है निर्माण कार्यों का प्रस्ताव– जिलाध्यक्ष**

**सीधी।** एक तरफ जहां राज्य शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए कई योजनाएं चालू कर उन्हें लाभान्वित किया जाता है वहीं ग्राम विकास के लिए राशि भी जारी की जाती है लेकिन राशि को वन विभाग द्वारा मनमानी तरीके से निर्माण कार्यों के जरिए ठिकाने लगाया जाता है और उपयोगिता विहीन एवं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जाता है। हाल ही में वन परिक्षेत्र मझौली अंतर्गत बीट चमराडोल में नव निर्मित स्टाफ डेम को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि जिस नाले में स्टाफ डैम का निर्माण हुआ है उससे महज 100 मीटर की दूरी पर बारहमासी बनास नदी बह रही है जहां पानी संरक्षण का कोई औचित्य ही नहीं है इसके साथ ही वीरान स्थान में निर्माण कार्य कराया गया है जहां उसकी उपयोगिता शून्य है इतना ही नहीं रोजगार को लेकर भी सवाल उठाया गया है कि पूरा निर्माण कार्य मशीनरी(मिलर)से कराया गया है ऐसे में रोजगार सृजन भी नहीं हुआ है।

### पीसीसी सड़क निर्माण में मनमानी

बीट नौढ़िया एक माह पूर्व भुर्सीडोल पहुंच मार्ग में वन सीमा में पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है जहां प्राक्कलन को दरकिनार कर गुणवत्ताविहीन कार्य कर वास्तविकता छुपाने के लिए नवनिर्मित सड़क में मिट्टी मुरूम की मोटी परत डाली गई है जबकि किसी भी पीसीसी सड़क में इस तरह मिट्टी नहीं डाली जाती है वहीं जिस स्थान में सड़क बनी है वहां कंकरीली एवं ढलान युक्त जमीन है जहां ना तो कीचड़ होता है और ना ही उस स्थान पर उसकी उपयोगिता थी फिर भी निर्माण कार्य के नाम पर लगभग 18 लाख से ऊपर की राशि ठिकाने लगाई गई है।उपरोक्त सड़क के गुणवत्ता एवं उपयोगिता को लेकर भी ग्रामीणों ने जांच कार्यवाही की मांग की है। मामले के संबंध में रेंजर एवं एसडीओ से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं की गई।

### गुणवत्ता पर भी सवाल

ग्रामीणों ने निर्माण कार्य के गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया है कि निर्धारित मापदंड एवं प्राक्कलन के मुताबिक निर्माण कार्य नहीं कराया गया है वहीं पारदर्शिता को भी छुपाया गया है क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी सूचना पटल में कोई जानकारी दर्ज नहीं की गई है। मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य की उपयोगिता एवं गुणवत्ता की जांच जिला प्रशासन से किए जाने की मांग की है।

## बरेली में 28वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविरः सुप्रिया ऐरन की प्रेरणादायक उपस्थिति समाजसेवा को मिला नया उत्साह

लोकतंत्र की शान

**(बरेली संदीप चंद्रा उत्तर प्रदेश)**पूर्व मेयर श्रीमती सुप्रिया ऐरन जी ने आज प्रयास रेवो एवं IMA बरेली द्वारा यांत्रिक कारखाना, इज्जतनगर में आयोजित 28वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। समाजसेवा के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जनहित के प्रति समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है।

श्रीमती ऐरन जी ने प्रयास रेवो और IMA बरेली की पूरी टीम के इस महान सामाजिक योगदान के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। ऐसे जनसेवी प्रयास ही समाज को नई दिशा और मानवता को नई शक्ति देते हैं। कहा दोनों संस्थायें समाज के लिए ये बड़ा सामाजिक योगदान हर साल करती रहती हैं

# संजय टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में बेरोंकटोक ग्रामीणों का प्रवेश

**» जंगल क्षेत्र की व्यवस्थाओं में बनी हुई है मनमानी,**
**» कोर क्षेत्र में ग्रामीणों के आने से वन्यजीवों का भारी खतरा**

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

**सीधी।** सीधी जिले की पहचान बना संजय टाइगर रिजर्व में आजकल मैदानी अमले की मनमानी से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। विशेष संरक्षित वन क्षेत्र जहां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति का प्रवेश भी वर्जित होता है। वहां कोर क्षेत्र में बाहर से आए हुए लोग महुआ बिनते हैं। यही नहीं महुआ बिनने वाले लोग कोर क्षेत्र के गांवो के अलावा आसपास के 10 किलोमीटर दूर के ग्रामों से भी कैंप डालकर महुआ बीनने से भी परहेज नहीं करते। जंगल में आग लगाकर पेड़ों के नीचे सफाई करते हैं। यही आग फैलकर हजारों हेक्टेयर जंगल जला देती है। आग में काबू पाने का प्रयास ना बीट गार्ड करते हैं ना चौकीदार या फायर वाचर। प्रायः बीट गार्ड वन क्षेत्र की चौकियो से गायब रहते हैं और बिना विभागीय अनुमति के शादी ब्याह के निमंत्रण में चले जाते हैं। साथ ही पेंड्रा ताल से बघनाद तक और बहेरवार में लोहराधार जो बाघों का सर्वोत्तम रहवास है। जलकर खाक हो गया। वन्यजीवो से भरा हुआ दुबरी रेंज का चारागाह वन क्षेत्र जानवरों की संख्या के अनुपात में अत्यधिक कम हो गया। चीतल कमजोर और बीमार दिखने लगे।

### पानी की कमी से वन्यजीवों का बना भटकाव

गर्मी में पानी की समस्या से वन्य जीवों को अत्याधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे-मोटे नदी नाले सूख जाते हैं। कुछ मुख्य नदी नालों का पानी बचता है। वहां भी ग्रामों के मवेशी प्रवेश कर जाते हैं। विभाग द्वारा कुछ कृत्रिम जल स्रोत बनाए गए थे। जिस ओर वर्तमान वन प्रबंधन का ध्यान नहीं है। सोसर बनाए गए जिनको टैंकर से पानी भरा जाता था पर वर्तमान में कभी कभार इस इन स्थानों में पानी डाला जाता है इसलिए ज्यादा समय तक सूखे पड़े रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाकर जलस्रोत बनाएं गए थे। जो 80 प्रतिशत बिगड़े हुए पड़े हैं। किसी को बंदरों ने तोड़ा किसी को हाथियों ने कोई रख रखाव की कमी से खराब हो गया पर विभाग एक बार लगाकर सोलर पैनल को भगवान भरोसे छोड़ दिया। कोर क्षेत्र में वनोपज का दोहन और अवैध प्रवेश वर्जित होता है परंतु पूरे संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में परिधि के ग्रामों से आए हुए लगभग दस हजार लोग कोर क्षेत्र के दूरस्थ जंगल तक प्रवेश कर तेंदूपत्ता तोड़ते हैं। जिन्हें किसी प्रकार से रोकने का प्रयास वन प्रशासन नहीं करता है।

### छोटे वन्यजीवों के सुरक्षा को लेकर लापरवाही

संजय टाईगर रिजर्व क्षेत्र में सैकड़ों प्रजाति के छोटे वन्यजीव बहुतायत में हैं। छोटे वन्यजीव अधिकांशतः टाइगर रिजर्व क्षेत्र से निकलकर आबादी क्षेत्र के आसपास भी रात में विचरण करने के लिए निकल जाते हैं। इनसे समीपी आबादी क्षेत्र को भी कोई खतरा न होने से लोग परवाह नहीं करते। यह दीगर बात है कि छोटे वन्यजीवों का अवैध शिकार आबादी क्षेत्र के आसपास कई बार हो जाता है। छोटे वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर यहां तैनात वन अमला भी ज्यादा गंभीर नहीं रहता। इसी वजह से इसको लेकर लापरवाही हमेंशा से बनी रही। बीट गार्डों को जिनको अपने क्षेत्र में वन्य जीवों पर नजर रखनी चाहिए साथ में वहां के वन क्षेत्र भी सुरक्षित रहें इस पर पैनी नजर रखी जानी चाहिए। टाईगर रिजर्व क्षेत्र में इस बात को लेकर कभी भी गंभीरता नहीं रही और यह लापरवाही कई बार भारी पड़ जाती है।

## संक्षिप्त समाचार

### नेपाल के राष्ट्रपति ने तीन और अध्यादेश जारी किये

**काठमांडू।** नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने देश की बालेन्द्र शाह सरकार द्वारा भेजे गये तीन और अध्यादेशों को हस्ताक्षर करके जारी कर दिया है। इस प्रकार से राष्ट्रपति भवन में लंबित आठ में से 6 अध्यादेश को जारी हो गये हैं जबकि दो अध्यादेश अब भी लंबित हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार जारी किए गए अध्यादेशों में स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से संबंधित कुछ नेपाली कानूनों में संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा विश्वविद्यालयों से संबंधित कुछ नेपाली कानूनों में संशोधन अध्यादेश शामिल हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य ने जानकारी दी कि सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान की धारा 114 की उपधारा 1 के तहत ये तीन अध्यादेश जारी किए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा आज शनिवार को जारी किए गए अध्यादेश से अब पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा की गईं सभी प्रकार की राजनीतिक और संवैधानिक नियुक्तियों को एक साथ खारिज किया जा सकता है। इससे पहले भी राष्ट्रपति पौडेल सहकारी एवं खरीद संबंधी अध्यादेश जारी कर चुके हैं। सरकार ने अन्य कुछ अध्यादेश जारी करने के लिए भी राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश भेजी थी। इनमें संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश भी शामिल था। बताया गया है कि राष्ट्रपति ने कुछ विधि विशेषज्ञों को शीतल निवास बुलाकर अध्यादेशों पर चर्चा भी की थी। हालांकि, राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश शुक्रवार और शनिवार को जारी किए गए निर्णयों की सूची में शामिल नहीं है।

### नेपाल के सल्यान पुलिस कार्यालय परिसर की खुदाई में 86 सॉकेट बम मिले

**काठमांडू।** नेपाल के सल्यान जिला पुलिस कार्यालय परिसर में भवन निर्माण के लिए नींव की खुदाई के दौरान शनिवार को बड़ी मात्रा में बम बरामद हुए। जिला पुलिस कार्यालय सल्यान ने बताया कि पूर्वाह्न 11:20 बजे तक कुल 86 सॉकेट बम बरामद किए जा चुके थे। जिला पुलिस कार्यालय सल्यान के प्रमुख डीएसपी डॉ. हेमबहादुर केसी ने बताया कि यह बम शारदा नगरपालिका स्थित जिला पुलिस कार्यालय परिसर में निर्माण कार्य के दौरान मिले। बुधवार दोपहर पुलिस परिसर में संदिग्ध वस्तु दिखाई देने के बाद

खुदाई शुरू की गई थी। खुदाई के दौरान 7 रेडियो वेव उपकरण, लगभग 500 ग्राम विस्फोटक पदार्थ, करीब 2 किलो बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और 10 मीटर फायरिंग केबल भी बरामद किए गए हैं। घटना सार्वजनिक होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उच्च सतर्कता अपनाई है। प्रारंभिक चरण में पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था। इसके बाद नेपाली सेना के मेजर कृष्ण क्षेत्री के नेतृत्व में सेना की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। आगे की खुदाई में अतिरिक्त 10 सॉकेट बम मिलने पर बम निष्क्रिय करने के लिए विशेष टीम बुलाई गई। दांग जिला से सेना के बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया है और शनिवार सुबह से विभिन्न टीम भी घटनास्थल पर तैनात है। पुलिस के अनुसार बरामद सभी विस्फोटक सामग्रियों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की तैयारी की जा रही है।

### 9 राज्यों में आंधी-बारिश, एमपी में गोदाम की छत उड़ी

**भोपाल/लखनऊ/शिमला/देहरादून।** भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश से राहत मिली। 9 राज्यों में आंधी-बारिश आई। कई जगह ओले गिरे। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन और बालाघाट में बारिश हुई। कई जगह आंधी भी आई। रायसेन में तेज आंधी से गोदाम की छत उड़ गई, किसानों का गेहूं भीग गया। बालाघाट और सीहोर में पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कश्मीर की चिनाब घाटी में लैंडस्लाइड के कारण डोडा-किश्तवाड़ रोड पूरी तरह बंद हो गई है। मलबे को हटाने के लिए मशीनें और कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के दोपहर एक बजे के बाद ललितपुर और झांसी में धूलभरी आंधी चली। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। झांसी मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा पेड़ स्कूटी और कार पर गिर गया। 15 जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32°C के बीच रहा। उरई 41.6°C के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर है, जबकि हरदोई में न्यूनतम तापमान सबसे कम 17°C रहा। 27 अप्रैल को बांदा में पारा 47.6°C पहुंचने के बाद पिछले 5 दिन में पारा 6°C तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने मई में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने और कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया है। साथ ही अलग-अलग इलाकों में टेम्परेचर मिला-जुला रहेगा। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। असम, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ अलग-अलग स्थानों पर (7-20 cm) बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान आया।

### केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ अपील खारिज

**नई दिल्ली/कोलकाता।** सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू (PSU) कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ TMC की आपत्ति को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते है। यह चुनाव आयोग का अधिकार है उन पर भरोसा करें।' TMC की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमें उनसे (चुनाव आयोग) से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। TMC ने इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने आपत्ति खारिज करते हुए कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसमें कोई अवैधता नहीं है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो फेज में चुनाव हुए हैं। रिजल्ट 4 मई को आएगा। चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अनुसार मतगणना की हर टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या पब्लिक सेक्टर (PSU) का होना अनिवार्य है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाए। टीएमसी ने यह शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी।

### जालंधर में लेडी ट्रेनर से अश्लील हरकत

**जालंधर।** जालंधर में एक कारोबारी ने लेडी जिम ट्रेनर के साथ भरे जिम में छेड़छाड़ की। वह पीछे से आया और लेडी जिम ट्रेनर को बाहों में भरकर पकड़ लिया। यह देखकर लेडी ट्रेनर भी हैरान रह गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर विरोध जताया। इसके बाद वह कारोबारी से बहस करते हुए नजर आई और तुरंत वहां से दूसरी तरफ चली गई। कारोबारी समझ गया कि लेडी ट्रेनर नाराज हो गई तो वह भी पीछे-पीछे जाता नजर आया। इस मामले का CCTV फुटेज भी सामने आया है। लेडी ट्रेनर का कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई, जिम में कई लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। कारोबारी ने पीछे से पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। जिम में मौजूद अन्य लोग भी इस घटना को देखकर दंग रह गए। उसने तुरंत इसकी शिकायत 112 पर कॉल कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कारोबारी हनी रंधावा को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लेडी जिम ट्रेनर शीशे के सामने मोबाइल देखने में व्यस्त है। इस दौरान हनी रंधावा तेजी से पीछे से आता है। वह अचानक जिम ट्रेनर को पीछे से आकर बाहों में भर लेता है। अचानक इस हरकत से जिम ट्रेनर भी हैरान रह जाती है। वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़ते हुए कुछ कहती है। इसके बाद वह वहां से जाने लगती है तो आरोपी उसे शांत करने की कोशिश करता है। मगर, लेडी ट्रेनर शांत नहीं हुई। वह बहुत गुस्से में नजर आ रही है। उसका गुस्सा देख कारोबारी पीछे हट जाता है। इसके बाद वह दूसरी तरफ चली जाती है।

# जर्मनी से नाराज अमेरिका ने 5000 सैनिक वापस बुलाए

## जर्मन चांसलर ने कहा था- ईरान ने अमेरिका की बेइज्जती की, अमेरिका की प्लानिंग भी बेकार

**एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी**

अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5,000 सैनिक हटाने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी होगी। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच बयानबाजी के बाद सामने आया है। मर्ज ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका के पास कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि वह इस जंग से बाहर कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत को टालने में माहिर है और अमेरिका को बिना नतीजे के इस्लामाबाद तक आना-जाना पड़ा। इससे अमेरिका को ईरान के सामने अपमानित होना पड़ा। इससे ट्रम्प नाराज हो गए थे। उन्होंने मर्ज को लेकर कहा कि वे बहुत खराब काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना अच्छी बात है। उन्हें हकीकत की समझ नहीं है। BBC के मुताबिक दिसंबर तक जर्मनी में 36,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात थे। यह संख्या जापान के बाद दूसरी सबसे बड़ी तैनाती है, जहां करीब 55,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा इटली में करीब 12,000 और ब्रिटेन में लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जर्मनी में अमेरिकी सैन्य ठिकाने लंबे समय से यूरोप में अमेरिका की रणनीतिक मौजूदगी का अहम हिस्सा रहे हैं। हालांकि, अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच ईरान को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। यूरोपीय देशों ने ईरान जंग में ट्रम्प का साथ देने के लिए कई बार इनकार किया है। जिसके बाद ट्रम्प आरोप लगाते आए है कि यूरोपीय देश केवल कागजी शेर है क्योंकि समय पर वह कभी काम नहीं आते। इसी बीच ट्रम्प ने इटली और स्पेन से भी सैनिक हटाने का संकेत दिया है। उनका कहना है कि ये देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, जिससे नाटो के भीतर मतभेद बढ़ते दिख रहे हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इससे पहले भी जर्मनी से सैनिक हटाने की बात कर चुके हैं। तब उन्होंने जर्मनी को दिवालिया कहा था क्योंकि वह नाटो के तय 2% रक्षा खर्च लक्ष्य से पीछे था। तब उन्होंने 12,000 सैनिकों को हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी संसद के विरोध और लॉजिस्टिक दिक्कतों के कारण यह लागू नहीं हो पाई। बाद में राष्ट्रपति जो बाइडन ने 2021 में इस योजना को रोक दिया और फिर रद्द कर दिया। पिछले साल अमेरिका ने रोमानिया में भी अपने सैनिकों की संख्या कम करने का फैसला लिया था।

## छतरपुर में पिता ने कमरे में बंद कर लगाई आग, मां ने फोन पर चीखें सुनी

**एजेंसी, छतरपुर**

**पड़ोसियों ने जान बचाई**

छतरपुर जिले के नौगांव के तिवारी मोहल्ले में शुक्रवार शाम करीब 5 बजे एक पिता ने अपने 8 और 5 साल के दो बेटों को किराए के कमरे में बंद कर आग लगा दी। उसी समय बच्चों की मां का फोन आया, जिसमें उसने उनकी चीखें सुनीं। घर से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। आग बुझाकर दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में बच्चे और आरोपी पिता हल्के झुलस गए। दोनों बच्चों को नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां वे खतरे से बाहर हैं। पुलिस तांत्रिक के कहने पर घटना को अंजाम देने के एंगल से जांच कर रही है।

**पति को फोन किया, दूसरी तरफ बच्चों की चीखें सुनीः** पलेरा थाना क्षेत्र निवासी राघवेंद्र तिवारी, पत्नी के मायके जाने के बाद, अपने बेटों जय (8 साल) और हर्ष मणि (5 साल) को लेकर छतरपुर रोड स्थित धर्म कांटा के पास तिवारी मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहा था। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे उसने बच्चों को कमरे में बंद कर आग लगा दी। उसी दौरान पत्नी ने उसे फोन किया, तो दूसरी तरफ से बच्चों की चीखें सुनाई दीं- "मम्मी... बचाओ... पापा मत जलाओ...।"

**पत्थर लेकर पड़ोसियों को रोकने लगा, बोला- क्यों बचा रहेः** घर से धुआं उठता देख पड़ोसियों को अनहोनी का अंदेशा हुआ। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे। कमरे में चारों तरफ धुआं भरा था और दोनों बच्चे कोने में सिमटे थे। आग तेजी से फैल रही थी। पड़ोसियों ने आग बुझाई और बच्चों को बाहर निकाला।

इस दौरान बच्चों के हाथ-पैर हल्के झुलस गए। घटना के समय आरोपी पिता भी कमरे में था और वह भी झुलस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब लोग बच्चों को बचाने पहुंचे तो वह पत्थर लेकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, "क्यों बचा रहे हो।"

## पुणे में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या, 65 साल का आरोपी गिरफ्तार

**एजेंसी, पुणे**

**सीएम बोले- सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी**

महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची से रेप के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 65 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची पुणे के भोर तहसील में रहने वाली अपनी नानी के यहां गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। भीमराव कांबले (आरोपी) शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर के पास बने तबेले में ले गया। वहां बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी (एसपी) नेता अनिल देशमुख ने मामले में आरोपी के लिए फांसी और मामला की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की थी। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराएगी और अपराधी के लिए फांसी की मांग करेगी।

तबेले से मिला बच्ची का शव काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ लोगों ने तबेले में भी बच्ची को तलाशा तो उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की तलाश की तो एक फुटेज में आरोपी बच्ची को तबेले की ओर ले जाता हुआ नजर आया। पुलिस ने तुरंत भीमराव कांबले को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।

## मप्र के बरगी डैम क्रूज हादसे में 4 लापता लोगों की तलाश जारी, सेना की ली जा रही मदद

**एजेंसी, नई दिल्ली**

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में क्रूज हादसे के बाद लापता चार लोगों की तलाश शनिवार को भी जारी है। एनडीआरएफ-एसडीआरएफ के साथ सेना जवान भी सर्चिंग में जुटे हैं, लेकिन दोपहर तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तेज हवा और डैम में उठ रही लहरों के कारण रेस्क्यू में समस्या आ रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। हादसे को हुए 40 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब भी 3 बच्चों समेत चार लापता लोगों का पता नहीं चल पाया है। बरगी सिटी सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 7 बजे से सर्चिंग अभियान शुरू किया गया है। चारों लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ-एसडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद ली जा रही है। छोटी वोट होने के कारण तेज हवा में रेस्क्यू अभियान संभलकर चलाना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते डूब गया था। हादसे के वक्त क्रूज में 45 से अधिक पर्यटक मौजूद थे। शुक्रवार शाम तक चले राहत एवं बचाव अभियान के दौरान नौ लोगों के शव बरामद कर लिये थे, जबकि 28 लोगों को बचा लिया गया था। तीन बच्चों सहित चार लोग लापता हैं, जिनका खबर लिखे जाने तक पता नहीं चल सका है। शुक्रवार शाम को रेस्क्यू के दौरान तेज बारिश भी होने लगी, जिसके चलते सर्चिंग रोक दी गई थी। शनिवार सुबह ही सर्चिंग शुरू कर दी गई थी। फिलहाल चारों लापता लोगों की तलाश जारी है।

बरगी डैम हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें नीतू सोनी (43), निवासी कोतवाली, जबलपुर, सौभाग्यम अलागन (42), निवासी अन्नानगर, वेस्ट तारापुरम, तमिलनाडु, मधुर मैसी (62), निवासी खाजन बस्ती, नई दिल्ली, काकुलाझी (38) पत्नी कामराज, निवासी वेस्ट लैंड खमरिया, जबलपुर, रेशमा सैयद (66), निवासी सिविल लाइन, भसीन आर्केड, जैक्सन होटल के पास, शमीम नकवी (68), निवासी डेरखी, भोपाल, मरीना मैसी (39) पत्नी प्रदीप मैसी निवासी दिल्ली, त्रिशान (4 वर्ष) पुत्र प्रदीप मैसी निवासी दिल्ली और ज्योति सेन, निवासी फूटाताल, घमापुर के आगे जबलपुर शामिल हैं। वहीं, तीन बच्चे समेत 4 लोग अब भी लापता हैं। इनमें श्रीतमिल (5 वर्ष) पुत्र कामराज, कामराज पुत्र श्रीरामालिंगम, विराज सोनी (6 वर्ष) पुत्र कृष्णा सोनी और मयूरम (9 वर्ष) पुत्र परिमल शामिल हैं। इधर, हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण और पीड़ितों से मुलाकात के बाद देर शाम लापरवाही करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की। क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी बृजेन्द्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

## छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट, 4 जवान शहीद, इसमें डीआरजी के इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल शामिल

**एजेंसी, जगदलपुर**

**कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर पर माइनिंग हटाते समय हादसा**

छत्तीसगढ़ के कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर पर शनिवार को IED ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए। फोर्स शनिवार सुबह कोरोसकोडा के जंगल में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों की बिछाई गई IED को डिप्यूज करते समय अचानक जोरदार धमाका हुआ। मामला छोटेबेठिया थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

हादसे में घायल जवानों का तुरंत रेस्क्यू किया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण 3 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल जवान परमानंद कोर्राम को बेहतर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट गया था, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इस घटना पर पूर्व CM भूपेश बघेल ने सरकार पर सवाल उठाए, कहा कि नक्सलवाद के खत्म होने के राजनीतिक नारे से काम नहीं चलेगा।

**भूपेश बोले- राजनीतिक नारे से काम नहीं चलेगाः** इस घटना पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को समझना होगा कि नक्सलवाद के ख़त्म होने के राजनीतिक नारे से काम नहीं चलेगा। नक्सली अपने पीछे आतंक के जो अवशेष छोड़ गए हैं, उनसे मुक्ति का भी अभियान छेड़ना पड़ेगा। यह लड़ाई साझी है, लोकतंत्र विरोधी ताकतों का समूल नाश ही एकमात्र विकल्प है।

**बस्तर IG बोले- सूचना के आधार पर चल रहा था अभियानः** बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि, सर्च के दौरान सुरक्षाबलों को एक नक्सली डंप भी मिला है। सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मिले इनपुट के आधार पर पिछले कुछ महीनों से लगातार आईईडी बरामदगी का अभियान चलाया जा रहा है। आज का अभियान भी उसी का हिस्सा था। इस दौरान हादसा हुआ।

## सरकार ने रोहित जैन को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किया नियुक्त

**एजेंसी, नई दिल्ली**

केंद्र सरकार ने रोहित जैन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की गई है। जैन वर्तमान डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से शनिवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। एसीसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रोहित जैन को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल पद संभालने की तारीख यानी 3 मई, 2026 से शुरू होगा यानी अगले आदेश तक लागू रहेगा, जो भी पहले हो। रोहित जैन इस पद पर टी रबी शंकर का स्थान लेंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल आज को समाप्त हो गया। जैन इससे पहले दिसंबर 2020 से आरबीआई में कार्यकारी निदेशक (ईडी) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कार्यकारी निदेशक के तौर पर जैन ने सुपरविजन विभाग (रिस्क, एनालिटिक्स और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट) की जिम्मेदारी संभाली है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने डिप्टी गवर्नर पद के लिए चार कार्यकारी निदेशकों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें से रोहित जैन के नाम पर भी मुहर लगी है।

## हैदराबाद में 6,000 लोगों ने एक साथ किया भुजंगासन, बना एशिया रिकॉर्ड

**एजेंसी, हैदराबाद**

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिनों की उलटी गिनती के अवसर पर हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई। इस भव्य आयोजन में करीब 6,000 लोगों ने एक साथ 'भुजंगासन' कर नया एशिया रिकॉर्ड बनाया। यह कार्यक्रम मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों ने निर्धारित समय तक एक साथ भुजंगासन का अभ्यास करते हुए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया, जिसे आधिकारिक मान्यता भी प्राप्त हुई।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि लोगों को योग को अपनी दैनिक जीवनशैली में शामिल करने के लिए प्रेरित करना भी था। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के उच्चायोग के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जबकि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए योग साधकों और शरणार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। योगाभ्यास का नेतृत्व संस्थान के निदेशक डॉ. काशीनाथ ने किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को सही तरीके से आसन करने के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के अंत में कमलेश पटेल (दाजी), जो श्री राम चंद्र मिशन के अध्यक्ष हैं, के निर्देशन में सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस ध्यान सत्र ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया।

## गऊघाट क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की रेलवे भूमि मुक्त

**एजेंसी, प्रयागराज**

मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में रेलवे प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत शनिवार को प्रयागराज जंक्शन परिक्षेत्र के गऊघाट क्षेत्र में रेलवे की अनधिकृत रूप से कब्जाई गई भूमि को सफलतापूर्वक खाली कराया गया। इस महत्वपूर्ण अभियान को अपर मंडल रेल प्रबंधक (सामान्य) दीपक कुमार के समन्वय में जिला प्रशासन के सहयोग से प्रभावी तरीके से सम्पन्न कराया गया। संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल एवं सिविल प्रशासन की टीमों ने मौके पर उपस्थित रहकर कार्यवाही को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से अंजाम दिया।

जनसम्पर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान लगभग 6500 वर्ग मीटर रेलवे भूमि, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उक्त भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपये आंका गया है। यह कार्रवाई रेलवे सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में मंडल इंजीनियर वी.के. त्रिपाठी, सहायक मंडल इंजीनियर प्रवीन कुमार श्रीवास्तव एवं रामचंद्र सिंह, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता शशिकांत तिवारी, सत्य प्रकाश सहित रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के लगभग 20 कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल रहे। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से सहायक सुरक्षा आयुक्त सुरेश यादव एवं प्रभारी निरीक्षक अमित मीणा अपने स्टाफ (लगभग 24 कर्मियों) सहित उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन एवं सिविल पुलिस की ओर से सहायक पुलिस आयुक्त (अतरसुइया) निकिता श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार राजेश कुमार यादव सहित विभिन्न थानों कीडगंज, अतरसुइया, कोतवाली, धूमनगंज एवं खुल्दाबाद के प्रभारी निरीक्षक एवं लगभग 60 पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में अभियान को सम्पन्न कराया गया। पीआरओ ने बताया कि रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेलवे भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत कब्जा पूर्णतः अवैध है तथा ऐसे मामलों में भविष्य में भी कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण न करें एवं ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना सम्बंधित अधिकारियों को दें।

# नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 -1 मई 2026 को राजपत्र में अधिसूचित- भारत की नागरिकता व्यवस्था में डिजिटल युग का प्रवेशःव्यापक समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

- 2009 के नियमों में डिजिटल तकनीक, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन और प्रवासी भारतीयों की बढ़ती संख्या ने नए सुधारों की मांग पैदा क़ी
- नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026- नागरिकता से जुड़ी प्रक्रियाओं को कागज- आधारित प्रणाली से निकालकर पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, जिससे पारदर्शिता,गति और जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार की संभावना

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

**गोंदिया** – वैश्विक स्तरपर किसी भी राष्ट्र की स्थिरता, उसकी संप्रभुता और प्रशासनिक दक्षता का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी कानून-व्यवस्था और नागरिकता प्रणाली होती है। नागरिकता केवल एक कानूनी पहचान नहीं, बल्कि व्यक्ति और राज्य के बीच अधिकारों,कर्तव्यों और विश्वास का एक गहरा सामाजिक अनुबंध है। समय के साथ जब समाज,तकनीक, प्रवासन और वैश्विक संपर्क का स्वरूप बदलता है,तब यह आवश्यक हो जाता है कि नागरिकता से जुड़े कानून और नियम भी उसी अनुरूप अद्यतन किए जाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 1 मई 2026 को राजपत्र मेंनागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया गया है,जो न केवल प्रशासनिक सुधार का प्रतीक है बल्कि डिजिटल शासन और वैश्विक मानकों के अनुरूप एक बड़े परिवर्तन का संकेत भी है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत की नागरिकता व्यवस्था ऐतिहासिक रूप सेजटिल और बहुस्तरीय रही है,जिसमें जन्म,वंश,पंजीकरण और प्राकृतिकरण जैसे विभिन्न आधार शामिल हैं। 2009 में बनाए गए नियमों ने उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया था,लेकिन बीते डेढ़ दशक में डिजिटल तकनीक,अंतरराष्ट्रीय प्रवासन और प्रवासी भारतीयों की बढ़ती संख्या ने नए सुधारों की मांग पैदा कर दी थी।ऐसे में 2026 के नए नियम पुराने ढांचे को आधुनिक बनाने का प्रयास करते हैं। इन नियमों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह नागरिकता से जुड़ी प्रक्रियाओं को कागज-आधारित प्रणाली से निकालकर पूर्णतःडिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, जिससे पारदर्शिता, गति और जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार की संभावना है। साथियों बात अगर हम नए नियमों में सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण बदलाव को समझने की करें तो यह नाबालिगों से संबंधित है। अब किसी भी नाबालिग को एक ही समय में भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट रखने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रावधान पहली नजर में कठोर प्रतीत हो सकता है,लेकिन इसके पीछे एक स्पष्ट नीति दृष्टिकोण है। वैश्विक स्तरपर दोहरी नागरिकता और बहु-पासपोर्ट के मामलों में कई बार कानूनी विवाद,सुरक्षा चुनौतियां और पहचान से जुड़े प्रश्न उत्पन्न होते हैं।विशेष रूप से नाबालिगों के मामले में,जहां निर्णय अक्सर माता-पिता द्वारा लिया जाता है,वहां भविष्य में नागरिकता विवादों की संभावना अधिक रहती है। भारत सरकार का यह कदम इन संभावित जटिलताओं को पहले ही रोकने का प्रयास है। यह नियम नागरिकता की स्पष्टता को बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान में कोई अस्पष्टता न रहे। इस बदलाव के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है इसको समझने की करें तो,आधुनिक युग में, जहां अंतरराष्ट्रीयआतंकवाद साइबर अपराध और पहचान की चोरी जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं, वहां नागरिकता और पासपोर्ट की स्पष्टता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। दोहरे पासपोर्ट रखने की स्थिति में निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया जटिल हो सकती है, जिससे सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में यह नया नियम सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक मजबूत कदम माना जा सकता है। साथियों बात अगर हम नए नियमों का दूसरे प्रमुख स्तंभ को समझने की करें तो यह प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) प्रणाली का पूर्णतः डिजिटलीकरण है।ओसीआई कार्ड लंबे समय से उन भारतीय मूल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा रहा है, जो विदेशों में बस चुके हैं लेकिन भारत के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहते हैं। पहले ओसीआई कार्ड से जुड़ी प्रक्रियाएं काफी हद तक कागजी और समय लेने वाली थीं, जिसमें आवेदन,सत्यापन और अनुमोदन में लंबा समय लगता था। अब नए नियमों के तहत इन सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी।डिजिटल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह मानवीय त्रुटियों और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करता है। जब आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, तो प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा, आवेदकों को भी अपने आवेदन की स्थिति को रियल- टाइम में देखने की सुविधा मिलती है,जिससे अनिश्चितता और असुविधा सटिकता से कम होती है। साथियों बात अगर हम नए नियमों में 'ई-ओसीआई' की अवधारणा को समझने की करें तो यह भी एक क्रांतिकारी कदम है। इसके तहत आवेदकों को भौतिक कार्ड के साथ-साथ डिजिटल पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। यह न केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रशासनिक दक्षता को भी बढ़ाता है। डिजिटल पहचान प्रणाली भविष्य में अन्य सरकारी सेवाओं के साथ भी एकीकृत की जा सकती है, जिससे एक समग्र डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण संभव होगा। यह कदम भारत को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है।इसके साथ ही, नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना ओसीआई दर्जा छोड़ता है या सरकार द्वारा उसका ओसीआई दर्जा रद्द किया जाता है, तो उसे अपना कार्ड अनिवार्य रूप से संबंधित प्राधिकरण के पास जमा करना होगा। यह प्रावधान प्रशासनिक नियंत्रण और रिकॉर्ड की शुद्धता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति कार्ड वापस नहीं करता है, तब भी सरकार के पास उसे डिजिटल रूप से रद्द करने का अधिकार होगा। यह दर्शाता है कि सरकार ने न केवल प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया है,बल्कि उनकेअनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी मजबूत प्रावधान किए हैं।

साथियों बात अगर हम एक और महत्वपूर्ण सुधार को समझने की करें तो दस्तावेजों की डुप्लिकेट' प्रतियो की अनिवार्यता को समाप्त करना है। यह बदलाव छोटे स्तर पर दिख सकता है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक है।पहले आवेदकों को कई बार एक ही दस्तावेज की कई प्रतियां जमा करनी पड़ती थीं,जिससे समय औरसंसाधनों की बर्बादी होती थी। अब डिजिटल दस्तावेजों के माध्यम से यह प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। यह कदम 'ईज ऑफ डूइंग गवर्नमेंट' की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो नागरिकों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाता है। साथियों नए नियमों में बायोमेट्रिक आधारित फास्ट- ट्रैक इमिग्रेशन की सुविधा भी शामिल की गई है, जो विशेष रूप से ओसीआई कार्डधारकों के लिए उपयोगी होगी। बायोमेट्रिक डेटा के उपयोग से पहचान सत्यापन की प्रक्रिया अधिक सटीक और तेज हो जाती है, जिससे हवाई अड्डों और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर समय की बचत होती है। हालांकि, इसके साथ ही डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जाए और इसे किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से सुरक्षित रखा जाए।नए नियमों में अपील की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति का आवेदन अस्वीकार होता है, तो अब वह एक उच्च प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है, जहां उसे सुनवाई का अधिकार भी मिलेगा। यह प्रावधान प्रशासनिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी निर्णय के खिलाफ उचित मंच उपलब्ध हो। साथियों इन सभी सुधारों का समग्र उद्देश्य भारत की नागरिकता प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।आज के वैश्वीकरण के युग में, जहां लोग शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए सीमाओं के पार जा रहे हैं, वहां एक मजबूत और स्पष्ट नागरिकता प्रणाली अत्यंत आवश्यक हो जाती है। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, जहां प्रवासी भारतीयों की संख्या करोड़ों में है और उनका देश के साथ आर्थिक और सामाजिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।हालांकि, इन नियमों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। डिजिटल प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा,और उपयोगकर्ताओं की डिजिटल साक्षरता जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। विशेष रूप से ग्रामीण और कम विकसित क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित है, वहां इन नई प्रणालियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकता है। इसके लिए सरकार को जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता प्रदान करनी होगी।इसके अलावा, नाबालिगों के पासपोर्ट संबंधी नए नियमों को लेकर भी कुछ सामाजिक और कानूनी बहस हो सकती है। ऐसे परिवार, जहां माता-पिता अलग-अलग देशों के नागरिक हैं, उनके लिए यह नियम जटिलताएं पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में सरकार को स्पष्ट दिशानिर्देश और लचीले प्रावधान बनाने होंगे, ताकि नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। साथियों बात अगर हम संपूर्ण मामलों को अंतरराष्ट्रीय परिपेक्ष में देखने की करें तो कई देश अपनी नागरिकता नीतियों को सख्त और स्पष्ट बना रहे हैं, खासकर सुरक्षा और प्रवासन के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। भारत का यह कदम भी उसी वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जहां डिजिटल तकनीक का उपयोग करके प्रशासन को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा रहा है।यह न केवल भारत की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को एक व्यापक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए, जो प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यह नियम केवल प्रक्रियाओं में बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच और दृष्टिकोण का प्रतीक है, जिसमें नागरिकता को एक गतिशील और विकसित होने वाली अवधारणा के रूप में देखा गया है। यदि इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और उनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जाता है, तो यह भारत की नागरिकता प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

**-संकलनकर्ता लेखक**
**- क़र विशेषज्ञ स्तंभकार**
**साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक**
**चिंतक कवि संगीत माध्यमा**
**सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन**
**सनमुखदास भावनानीं गोंदिया**
**महाराष्ट्र 9284141425**

# स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की सेहत का आईना

लेखक - सौरभ वार्ष्णेय

प्रत्येक वर्ष 3 मई को पूरे विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह केवल एक औपचारिक अवसर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सेहत का आईना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक मीडिया किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। प्रेस की आज़ादी सिर्फ पत्रकारों का अधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों के जानने के अधिकार का विस्तार है। वहीं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 157 वें स्थान पर है। पिछले वर्ष (2025) के 151वें स्थान की तुलना में यह छह पायदान की गिरावट है। भारत में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, मीडिया के केंद्रीकृत स्वामित्व और राजनीतिक दबाव के कारण यह रैंकिंग बेहद गंभीर श्रेणी में है। आज जब दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, सूचना का प्रवाह पहले से कहीं अधिक तेज़ और व्यापक हो गया है। लेकिन इसी के साथ प्रेस की स्वतंत्रता पर नए प्रकार के खतरे भी मंडरा रहे हैं। फेक न्यूज़, ट्रोल संस्कृति, सत्ता का दबाव, कॉरपोरेट हितों का प्रभाव और पत्रकारों की सुरक्षा जैसे मुद्दे गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। कई देशों में पत्रकारों को सच्चाई उजागर करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है—यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां प्रेस न केवल सत्ता की निगरानी करता है, बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ भी बनता है। हालांकि, हाल के वर्षों में यह बहस तेज़ हुई है कि क्या मीडिया अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने में पूरी तरह सफल है? गोडी मीडिया जैसे शब्दों का प्रचलन इस चिंता को दर्शाता है कि कहीं न कहीं मीडिया का एक वर्ग सत्ता के अधिक निकट जाता दिख रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि वह बिना जिम्मेदारी के कार्य करे। स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होती है। पत्रकारिता का मूल धर्म सत्य की खोज, तथ्यों की पुष्टि और निष्पक्ष प्रस्तुति है। जब मीडिया सनसनीखेज़ता या पक्षपात की ओर झुकता है, तो वह अपने ही अस्तित्व को कमजोर करता है।

इस अवसर पर सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे पत्रकारों को सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण प्रदान करें, जहां वे बिना भय के अपना कार्य कर सकें। वहीं, मीडिया संस्थानों को भी आत्ममंथन करना होगा कि वे व्यावसायिक दबावों से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता दें। लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो उसकी आवाज़ को स्वतंत्र रखना ही होगा। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। लोकतंत्र किसी भवन की तरह है, जिसकी नींव जनता की भागीदारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिकी होती है। यदि इस अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया जाए, तो लोकतंत्र का ढांचा धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है।स्वतंत्र आवाज़ केवल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के विचार, प्रश्न और असहमति को व्यक्त करने के अधिकार का प्रतीक है। जब नागरिक बिना भय के अपनी बात कह पाते हैं, तभी सरकारें जवाबदेह बनती हैं और नीतियों में पारदर्शिता आती है। इसके विपरीत, जब आवाज़ों को दबाया जाता है, तो सत्ता निरंकुशता की ओर बढ़ने लगती है।आज के समय में यह चुनौती और भी जटिल हो गई है। एक ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति के नए अवसर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर दुष्प्रचार, ट्रोलिंग और सेंसरशिप जैसी प्रवृत्तियां भी सामने आई हैं। ऐसे में संतुलन बनाना आवश्यक है—जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, वहीं जिम्मेदारी और सत्यनिष्ठा भी सुनिश्चित हो।लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता; यह निरंतर संवाद, आलोचना और विचार-विमर्श की प्रक्रिया है। इसलिए जरूरी है कि हम न केवल अपनी आवाज़ को स्वतंत्र रखें, बल्कि दूसरों की आवाज़ को सुनने और सम्मान देने की संस्कृति भी विकसित करें।

# केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है पत्रकारिता की स्वतंत्रता

लेखक - योगेश कुमार गोयल

भारत में प्रेस को सदैव लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी जाती रही है क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती में इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बहुत अहम माना गया है लेकिन विड़म्बना है कि विगत कुछ वर्षों से यहां भी प्रेस स्वतंत्रता के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। इसीलिए प्रतिवर्ष 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' मनाया जाता है। कलम को तलवार से भी ज्यादा ताकतवर और तलवार की धार से भी ज्यादा प्रभावी इसीलिए माना गया है क्योंकि इसी की सजगता के कारण न केवल भारत में बल्कि अनेक देशों में पिछले कुछ दशकों के भीतर बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो सका, जिसके चलते बड़े-बड़े उद्योगपतियों, नेताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को एक ही झटके में अर्श से फर्श पर आना पड़ा। यही कारण हैं कि समय-समय पर कलम रूपी इस हथियार को भोथरा बनाने या तोड़ने के कुचक्र होते रहे हैं और विभिन्न अवसरों पर न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में सच की कीमत कुछ पत्रकारों को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है। पिछले दशकों में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में स्थितियां काफी बदल गई हैं। आज दुनियाभर में पत्रकारों पर राजनीतिक, अपराधिक और आतंकी समूहों का सर्वाधिक खतरा है और भारत भी इस मामले में अछूता नहीं है। विड़म्बना है कि दुनियाभर के न्यूज रूम्स में सरकारी तथा निजी समूहों के कारण भय और तनाव में वृद्धि हुई है। पेरिस स्थित 'रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स' (आरएसएफ) अथवा 'रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स' नामक संस्था द्वारा हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, वे सदैव चौंकाने वाले होते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि कुछ देश इस रिपोर्ट में जारी किए जाने वाले आंकड़ों को पूर्वाग्रह से प्रेरित बताकर खारिज भी करते रहे हैं। 'रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स' एक ऐसा गैर-लाभकारी संगठन है, जो विश्वभर के पत्रकारों पर हमलों का दस्तावेजीकरण करने और मुकाबला करने के लिए कार्यरत है और प्रतिवर्ष 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' अर्थात् 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' नामक रिपोर्ट पेश करता है। 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019' में उसने भारत सहित विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया था कि किस प्रकार विश्वभर में पत्रकारों के खिलाफ घृणा हिंसा में बदल गई है, जिससे दुनियाभर में पत्रकारों में डर बढ़ा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के अनुसार, 180 देशों की सूची में भारत 157वें स्थान पर खिसक गया है जबकि 2025 में भारत 151वें स्थान पर था यानी एक वर्ष में छह स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पूर्व 2024 में भारत 159वें, 2023 में 161वें और 2022 में 150वें पायदान पर खड़ा था। यह रिपोर्ट प्रेस स्वतंत्रता के लिए भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट का संकेत देती है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों के साथ व्यवहार के लिए 'संतोषजनक' माने जाने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है लेकिन ऐसी संख्या भी कम नहीं है, जहां स्थिति 'बहुत गंभीर' है। रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स द्वारा जारी दुनियाभर के देशों की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में भारत जहां 2024 में 2023 के मुकाबले दो पायदान ऊपर चढ़ा, वहीं 2023 में 2022 के मुकाबले 11 पायदान नीचे गिरा था और 2022 में भी 2021 की रैंकिंग के मुकाबले 8 स्थान नीचे फिसला था। 2021 की रैंकिंग में भारत का स्थान 142वां था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की सूची में नॉर्वे शीर्ष पर है। भारत के लोकतंत्र को तो दुनिया का सबसे सफल और बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहीं अगर नार्वे जैसा छोटा सा देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में लगातार शीर्ष स्थान पर विराजमान है और चीन को छोड़कर भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश भी बेहतर स्थिति में है तो यह स्थिति भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए सही स्थिति नहीं है। ऐसे में हमें गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है कि हम इस मामले में वर्ष दर वर्ष क्यों फिसल रहे हैं? प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में यह गिरावट स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता में कमी आने का सीधा और स्पष्ट संकेत यही है कि लोकतंत्र की मूल भावना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार निहित है, उसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। समाज में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ माना गया है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार खासकर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बगैर किसी जानकारी को जांचे-परखे केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए झूठ का बवंडर तैयार किया जाता है, उसे देखकर कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है मानो टीवी चैनल पर समाचार या कोई न्यूज कार्यक्रम नहीं बल्कि कोई मसालेदार राजनीतिक फिल्म चल रही हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा है कि लोगों का विश्वास मीडिया पर निरंतर कम हो रहा है और लोगों का आकर्षण सोशल मीडिया की ओर बढ़ रहा है, जहां पहले से ही फेक न्यूज बहुत बड़ी समस्या मौजूद है तथा एआई इस समस्या को और ज्यादा बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रही है। भारतीय संविधान में प्रेस को अलग से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है बल्कि उसकी स्वतंत्रता भी नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता में ही निहित है और देश की एकता तथा अखण्डता खतरे में पड़ने की स्थिति में इस स्वतंत्रता को बाधित भी किया जा सकता है किन्तु ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होने पर भी देश में पत्रकारिता का चुनौतीपूर्ण बनते जाना लोकतंत्र के हित में कदापि नहीं है बल्कि यह स्पष्ट रूप से कुछ शक्तियों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का ही प्रयास माना जाता है। कल्पना की जा सकती है कि प्रेस की स्वतंत्रता अगर इसी प्रकार सवालों के घेरे में रही तो पत्रकार कैसे पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को अंजाम देते रहेंगे? प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के प्रयासों के चलते कैसे सच को उजागर कर उसे निष्पक्ष तरीके से जनता तक पहुंचाया जाना संभव होगा? देश में प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रहे, इसके लिए किसी मीडिया संस्थान से जुड़े पत्रकार हों या स्वतंत्र पत्रकार, उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए जाने की सख्त दरकार है ताकि बगैर किसी दबाव या भय के पत्रकार अपना कर्त्तव्य बखूबी निभाते रहें। हालांकि यह भी बेहद जरूरी है कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ 'प्रेस' को भी अपनी सीमाओं और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपनी स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करना चाहिए। (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और 'सागर से अंतरिक्ष तकः भारत की रक्षा क्रांति' सहित कई पुस्तकों के लेखक हैं) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

# शांति के भविष्य का निर्माणः स्वतंत्र प्रेस की निर्णायक भूमिका

लेखक - सुनील कुमार महला

मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मजबूती के संदर्भ में हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि मीडिया केवल समाचार देने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह विश्व में शांति, पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करने का भी एक सशक्त व शानदार उपकरण है। कहना ग़लत नहीं होगा कि किसी भी देश में प्रेस की स्थिति उसके लोकतंत्र की मजबूती का असली दर्पण होती है, शायद यही कारण भी है कि इसे 'लोकतंत्र का आईना' भी कहा जाता है। वास्तव में, प्रेस की स्वतंत्रता सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी है, जो एक मौलिक मानव अधिकार है।सच तो यह है कि यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार भी है।पाठक जानते होंगे कि कई देशों में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि इस दिवस का मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को समझाना, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यदि हम इस दिवस के इतिहास पर दृष्टि डालें तो वर्ष 1991 में नामीबिया(अफ्रीका) में आयोजित सम्मेलन में 'विंडहोक घोषणा' को अपनाया गया था, जिसमें स्वतंत्र, बहुलवादी और मुक्त प्रेस का आह्वान किया गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में 3 मई को इस दिवस के रूप में घोषित किया। गौरतलब है कि यह प्रस्ताव यूनेस्को के 26वें महासम्मेलन में पारित किया गया था।यहां उल्लेखनीय है कि इस दिवस पर हर वर्ष एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वर्ष 2026 में यह सम्मेलन लुसाका (जाम्बिया) में आयोजित हो रहा है, जहां पत्रकार, तकनीकी विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और मानवाधिकार कार्यकर्ता एक साथ विचार-विमर्श करते हैं। इतना ही नहीं, इसी अवसर पर यूनेस्को द्वारा 'गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार' भी प्रदान किया जाता है, जो उन पत्रकारों को सम्मानित करता है, जिन्होंने जोखिम उठाकर सत्य को निष्पक्षता और निडरता से दुनिया के सामने उजागर किया।बहुत कम लोग जानते हैं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर वर्ष 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' जारी करता है, जिससे यह आकलन किया जाता है कि किस देश में मीडिया कितनी स्वतंत्र है। वास्तव में, यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आज एआइ व संचार क्रांति का दौर है और आज के डिजिटल युग में प्रेस की परिभाषा और स्वरूप दोनों बदल गए हैं। पहले जहां अखबार, रेडियो और टीवी प्रमुख थे, वहीं अब इंटरनेट और सोशल मीडिया भी 'डिजिटल प्रेस' का रूप ले चुके हैं। आम नागरिक भी अब सूचना के प्रसार में भागीदारी कर रहे हैं। इससे सूचना का प्रवाह तेज हुआ है, लेकिन 'फेक न्यूज़' और दुष्प्रचार का खतरा भी बढ़ गया है।कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) ने पत्रकारिता के क्षेत्र में नए अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा की हैं। यह खबरों के संग्रह और विश्लेषण को तेज बनाती है, लेकिन इसका दुरुपयोग गलत सूचनाएं फैलाने में भी हो सकता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिद्म यह तय करते हैं कि लोगों को कौन-सी खबर दिखाई जाएगी, जिससे 'अदृश्य नियंत्रण' का एक नया स्वरूप उभर रहा है। हर वर्ष इस दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है, जो समकालीन चुनौतियों को दर्शाती है। वर्ष 2025 की थीम थी-बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंगः प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। वास्तव में, यह थीम खास तौर पर इस बात पर केंद्रित थी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) पत्रकारिता, मीडिया और सूचना प्रणाली को कैसे बदल रही है।एआइ( आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)पत्रकारिता को तेज और प्रभावी बना रही है,लेकिन साथ ही फेक न्यूज़, डीपफेक और दुष्प्रचार जैसी चुनौतियाँ भी बढ़ा रही है।इस थीम का मुख्य संदेश था कि तकनीक का उपयोग इस तरह किया जाए कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को मजबूत करे, कमजोर नहीं।वहीं वर्ष 2026 की थीम है-शांति के भविष्य का निर्माणः मानवाधिकार, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। भारत के संदर्भ में, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। यह नागरिकों को बिना किसी भय के अपनी बात रखने का अधिकार देता है।हालांकि; राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर कुछ सीमाएं भी लागू होती हैं। गौरतलब है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारतीय प्रेस परिषद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसे संस्थान कार्यरत हैं।

राजस्थान-दिल्ली मैच के बाद अंक तालिका

# राहुल का ऑरेंज कैप पर कब्जा

### भुवनेश्वर का दबदबा बरकरार



**नई दिल्ली।** इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 43वें मैच में शुक्रवार (1 मई) को दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स के 9 मैच में 8 अंक हो गए। वह अंक तालिका में छठे नंबर पर हैं। राजस्थान रॉयल्स के 10 मैच में 6 जीत हैं। वह चौथे नंबर पर है। पंजाब किंग्स शीर्ष पर बरकरार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स आखिरी पायदान पर है।

ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो केएल राहुल पहले नंबर पर है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा लिया। अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। पर्पल कैप की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार शीर्ष पर हैं। जोफ्रा आर्चर और ईशान मलिंगा के 15-15 विकेट हैं।

नीचे अंक तालिका, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप रेस की जानकारी दी गई है।

### पंजाब किंग्स शीर्ष पर, चार टीमें प्लेऑफ की दौड़ में

पंजाब किंग्स 8 मैचों में 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स – तीनों 12-12 अंकों पर हैं। शीर्ष चार में जगह के लिए हक्र्क निर्णायक भूमिका निभाएगा।

| क्र | टीम | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पंजाब किंग्स | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | +1.043 |
| 2 | रॉ. चैलेंजर्स बेंगलुरु | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | +1.420 |
| 3 | सनराइजर्स हैदराबाद | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | +0.832 |
| 4 | राजस्थान रॉयल्स | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +0.510 |
| 5 | गुजरात टाइटंस | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | -0.192 |
| 6 | दिल्ली कैपिटल्स | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | -0.895 |
| 7 | चेन्नई सुपर किंग्स | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -0.121 |
| 8 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | -0.751 |
| 9 | मुंबई इंडियंस | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -0.784 |
| 10 | लखनऊ सुपर जायंट्स | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -1.10 |

## स्टार्क का यशस्वी ने गगनचुंबी शॉट से किया स्वागत

- मैच में पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले 5वें बल्लेबाज बने

**नई दिल्ली।** इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का स्वागत छक्के से किया। यशस्वी ने मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा। हालांकि, वह तीसरी ही गेंद पर पवेलियन लौट गए, लेकिन बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जायसवाल आईपीएल मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ने वाले पांचवें बल्लेबाज बने। सबसे पहले यह कारनामा नमन ओझा ने 2009 में किया था। राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए ओझा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ब्रेड हॉज को छक्का जड़ा था। विराट कोहली ने 2019 में वरुण एरोन को पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। यह मैच बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए फिल साल्ट ने 2024 में नुवान तुषारा को पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। यशस्वी जायसवाल ने चौथी बार पारी की शुरुआत छक्के से की 2025 में पंजाब किंग्स के लिए ओपनिंग करते हुए प्रियांश आर्या ने चेन्नई सुपर किंग्स के खलील अहमद को छक्का जड़ा था। यशस्वी जायसवाल ने चौथी बार पारी आईपीएल मैच की पारी में पहली गेंद पर छक्का जड़ा। प्रियांश आर्या ने 2 बार छक्का जड़ा है। नमन ओझा, मयंक अग्रवाल, सुनील नरेन, विराट कोहली, रॉबिन उथप्पा, फिल साल्ट और संजू सैमसन ने 1–1 छक्के जड़े।

व्यापार

**बिजनेस क्लास पर भी डिस्काउंट**

## एयर इंडिया का बड़ा प्लान, बिना खाना लिए बुक कर सकेंगे टिकट, कम से कम 250 बचेंगे

**नई दिल्ली, एजेंसी।** मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में जारी तनाव का असर अब एविएशन सेक्टर पर भी साफ दिखने लगा है। बढ़ती लागत और गिरते राजस्व के बीच एयर इंडिया यात्रियों को राहत देने के लिए बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एयर इंडिया ने अपनी लागत घटाने और यात्रियों को सस्ते टिकट उपलब्ध कराने के लिए घरेलू और छोटी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (2 घंटे से कम) में भोजन को वैकल्पिक बनाने की योजना बना रही है।

### कितनी सस्ती होगी टिकट

सूत्रों के मुताबिक इस अनबंडलिंग (सुविधाओं को अलग करना) प्रक्रिया के लागू होने के बाद यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। सबसे ज्यादा असर टिकट की कीमत पर दिखाई दे सकता है। जो यात्री उड़ान के दौरान खाना नहीं चुनेंगे, उनके टिकट की कीमत में 250 रुपये या उससे अधिक की कटौती हो सकती है। यह बदलाव अगले एक-दो महीनों में शुरू होने की उम्मीद है।

एयर इंडिया न केवल इकोनॉमी क्लास, बल्कि बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए भी बचत के रास्ते तलाश रही है। एयरलाइन लाउंज एक्सेस को भी टिकट से अलग करने पर विचार कर रही है। मेट्रो एयरपोर्ट पर लाउंज संचालक



औसतन 1100 से 1400 रुपये प्रति यात्री चार्ज करते हैं। कई बिजनेस यात्री सीधे उड़ान के समय एयरपोर्ट पहुंचते हैं और लाउंज का उपयोग नहीं करते। ऐसे में उन्हें बिना लाउंज सुविधा वाला सस्ता टिकट खरीदने का विकल्प मिल सकता है।

महंगे एटीएफ और कुछ देशों के बंद एयर स्पेस की वजह से हर दिन करोड़ों रुपये का घाटा उठा रही एयर इंडिया ने मई महीने में करीब 150 इंटरनेशनल फ्लाइटों में कटौती की है। यह कटौती दिल्ली, मुंबई समेत अहमदाबाद और अन्य एयरपोर्ट से अमेरिका, कनाडा और यूरोप जाने वाली लंबी दूरी की फ्लाइटों में की गई है। एयरलाइंस ने पूरी तरह फ्लाइट बंद नहीं की है बल्कि फ्रीक्वेंसी कम की है। जहां पहले हफ्ते में 4-5 फ्लाइट चलती थीं, वहां अब लोड फैक्टर के हिसाब से 1-2 फ्लाइट कम की गई है।

**एयर इंडिया क्यों ले रही है ये फैसले:** 28 फरवरी के बाद से एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में उछाल और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने एयरलाइंस की परिचालन लागत को काफी बढ़ा दिया है।

भारत एक बेहद संवेदनशील बाजार है। टिकट की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने पर लोग हवाई यात्रा के बजाय ट्रेन या सड़क मार्ग चुनना शुरू कर देते हैं। एयरलाइन नहीं चाहती कि ऊंचे किराये की वजह से यात्री कम हों।

दुनिया भर की कई बड़ी 'फुल सर्विस' एयरलाइंस अब अपनी सेवाओं को अनबंडल कर रही हैं। कई एयरलाइंस केवल बेसिक मील देती हैं और विशेष फूड के लिए अलग से शुल्क लेती हैं। जानकारों का कहना है कि अब 'फुल सर्विस' और 'लो-कॉस्ट' (जैसे इंडिगो) एयरलाइंस के बीच का अंतर तेजी से खत्म हो रहा है।

## रिटायरमेंट की उम्र 65 और ओल्ड पेंशन का मिलेगा तोहफा...8वें वेतन आयोग पर नजर

**नईदिल्ली, एजेंसी।** केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवें वेतन आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। वेतन आयोग से अलग-अलग कर्मचारी संगठन डिमांड कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन ने भी एक डिमांड लिस्ट दी है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प मिलना चाहिए। इसके अलावा, केंद्र सरकार के शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल की जानी चाहिए। इस संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार के अपने कर्मचारियों के लिए जारी सभी आदेशों में साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन तीन मांगों के अलावा, कर्मचारी संगठन अपनी पहले की मुख्य मांगों पर भी कायम रहा। बता दें कि कर्मचारी संगठन ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर, 69,000 रुपये



का न्यूनतम मूल वेतन और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 6 प्रतिशत-7 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की है। ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि हम चाहते हैं कि वेतन आयोग केंद्र सरकार के सब्सक्राइबर्स को सेवा के कुछ साल पूरे करने के बाद जाने का विकल्प दें। पटेल के मुताबिक ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन की पहली मांग को खत्म करने की थी, जिस पर 8वां वेतन आयोग सहमत नहीं हुआ। पटेल बताते हैं कि इस तरह के विकल्प का सुझाव देने की वजह यह है कि मार्केट से जुड़ा हुआ है और अगर किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय मार्केट लंबे समय तक नीचे रहता है, तो उनके पास कम पेंशन लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। पटेल ने मांग की है कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट के समय से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करते हैं उनके लिए सुझाव है कि उनकी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा, साथ ही महंगाई भत्ता पेंशन के तौर पर दिया जाए। वेतन आयोग से मांग की गई है कि केंद्र सरकार के शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी जाए।

## डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को दिया झटका, कारों और ट्रकों पर टैरिफ 25 प्रतिशत बढ़ेगा

**नई दिल्ली, एजेंसी।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (ईयू) को झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगले हफ्ते ईयू से इंपोर्ट होने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25 फीसदी



कर देगा। उन्होंने दावा किया कि यह ग्रुप पहले से तय ट्रेड डील का पालन नहीं कर रहा है। भारत के लिए भी इसके मायने हैं। यह फैसला भारत के लिए 'चुनौती और अवसर' दोनों लेकर आया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यूरोपियन यूनियन हमारी पूरी तरह से तय ट्रेड डील का पालन नहीं कर रहा है, अगले हफ्ते मैं अमेरिका में ईयू से आने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ा दूंगा।' उन्होंने आगे कहा, 'टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा।' ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्लांट में बनने वाले वाहनों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा।

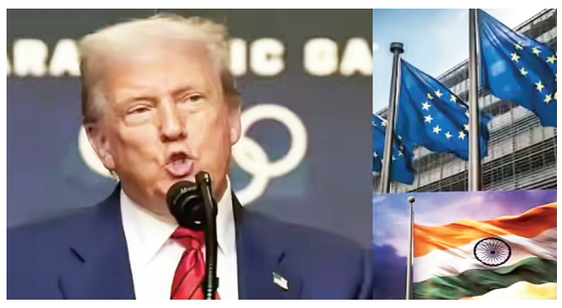

उनके मुताबिक, 'यह पूरी तरह से समझा और माना गया है कि अगर वे अमेरिका के प्लांट में कारें और ट्रक बनाते हैं तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा।'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि देश में कई ऑटोमोबाइल और ट्रक बनाने वाले प्लांट बनाए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, 'अभी कई ऑटोमोबाइल और ट्रक प्लांट बन रहे हैं। इनमें 100 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। यह कार और ट्रक बनाने के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।' अमेरिका-ईयू के व्यापार संबंधों में आएगा तनाव इस नए कदम से अमेरिका और ईयू के ट्रेड संबंधों पर फिर से दबाव बढ़ गया है। खासतौर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में यह बात लागू होती है। यूरोपियन ब्रांडों की अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट के मामले में मजबूत मौजूदगी है। इसका नाम स्कॉटलैंड में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के नाम पर रखा गया था। हालांकि, 2025 की डील की स्थिति पर तब सवाल उठने लगे, जब इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रंप के पास टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है।

## भारत का बड़ा दांव, तंजानिया के साथ लोकल करेंसी में लेन-देन का प्लान, चीन को लगेगा करंट

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत और तंजानिया द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बड़े प्लान में जुट गए हैं। नई दिल्ली ने इस पूर्वी अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन-देन निपटाने पर चर्चा की है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह बताया गया। यह कई मायने में बेहद अहम है। चीन तंजानिया सहित अफ्रीकी देशों में अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगा है। भारत के साथ इस तरह की चर्चा शायद चीन को अच्छी नहीं लगेगी। भारत तंजानिया के कृषि उत्पादों (दालें, काजू) का बड़ा खरीदार है। चीन की वहां के रणनीतिक खनिजों पर नजर है। बीजिंग इन्हें अपनी ओर मोड़ने के लिए आर्थिक कूटनीति का सहारा ले रहा है। भारत अगर अपनी योजना पर आगे बढ़ता है तो यह चीन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाला होगा।

### मंत्रालय ने क्या बताया है

चर्चाओं में स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन–देन को बढ़ावा देने का विषय शामिल था।' मंत्रालय ने आगे कहा कि माइनिंग सेक्टर में सहयोग, रत्न क्षेत्र में वैल्यू एडिशन, रत्नों के निर्यात से जुड़े रेगुलेटरी डेवलपमेंट के साथ क्षमता निर्माण और कौशल विकास के अवसरों पर भी चर्चा की गई।





### भारत ने क्या किया है ऑफर

भारत ने जहाज निर्माण के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की। जहाज निर्माण स्थलों (शिपयार्ड) के विकास और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे पर जोर देने के साथ तंजानियाई संस्थानों के साथ संभावित साझेदारियों पर भी रोशनी डाली। मंत्रालय ने बताया कि भारत ने लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक की सप्लाई, रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विशेष संस्थानों के जरिये क्षमता निर्माण में भी सहयोग देने की पेशकश की। दोनों देशों के बीच वर्ष 2024–25 में 8.64 अरब अमेरिकी डॉलर रहा द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर वर्ष 2025–26 में 9.02 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

### तंजानिया में बड़ा खिलाड़ी है चीन

चीन तंजानिया का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साथ ही प्रमुख विदेशी निवेशक भी है। वह वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और खनिज खनन (जैसे ग्रेफाइट और सोना) में भारी निवेश कर रहा है। चीन ने मई 2026 से तंजानिया सहित अफ्रीकी देशों के लिए 'जीरो–टैरिफ' पॉलिसी लागू की है। इसका उद्देश्य तंजानिया के संसाधनों पर अपना कंट्रोल मजबूत करना और भारत जैसे प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ना है। लंबी अवधि के व्यापार वीजा की सुविधा देने, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में नियामक सहयोग को मजबूत करने के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और जहाज निर्माण के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर भी चर्चा की है। इन मुद्दों पर 29–30 अप्रैल, 2026 को तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित भारत–तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के दौरान विचार–विमर्श किया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)